अंतरराष्ट्रीय व्यापार

7
अध्याय

वैश्विक आर्थिक संकट के बाद के दो वर्षों के दौरान कम स्तर पर बने रहने के बाद वस्तुओं और सेवाओं दोनों में विश्व व्यापार 2011 का संकट पूर्व स्थिति पर पहुंच गया और उसे भी पार कर गया। तथापि, 2012 में वैश्विक विकास दर और व्यापार में कमी आने तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक विकासदर के फिर से गति पकड़ने की दर धीमी रहने के संबंध में पूर्वानुमान में विश्व व्यापार क्षीण रहने तथा मंद गति से पूर्व स्थिति को प्राप्त करने का पूर्वाभास प्राप्त हुआ। भारत द्वारा निर्यात जो 40.5 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर से 2010-11 के एक वर्ष के भीतर संकट पूर्व स्तर को पार कर गया तथा 2011-12 में भी इसमें वृद्धि जारी रहेगी किंतु 2009-10 के संकट ग्रस्त वर्ष (पूर्ण वर्ष) के दौरान रिकार्ड किए गए -3.5 प्रतिशत की तुलना में पहले दस महीनों में -4.9 प्रतिशत से भी अधिक की दर से निर्यात गिरावट से 2012-13 में आई वैश्विक मंदी द्वारा अंतत: प्रभावित हुआ।

विश्व व्यापार

7.2 विश्व पण्य व्यापार का मूल्य 16 ट्रिलियन अमरीकी डालर के संकट पूर्व स्तर (2008) को पार कर गया और इस प्रकार दो वर्षों के अंतराल के पश्चात 2011 में 18.26 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। तथापि विश्व व्यापार की मात्रा 2012 में तेजी से गिर कर दर 2.8 प्रतिशत हो गई जबकि 2011 में यह 5.9 प्रतिशत और 2010 में 12.6 प्रतिशत थी। (सारणी 7.1)

7.3 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी आर) के आंकडों के अनुसार विश्व निर्यात में 2012 की पहली तीन तिमाहियों में 2011 की तदनुरूपी आस्तियों की तुलना में 0.2 प्रतिशत की कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जनवरी 2013 के अदयतन आंकड़ों के अनुसार, 2013 में विश्व व्यापार मात्रा में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जो अक्तूबर 2012 के आंकड़ों की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम है। हालांकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था की आयात और निर्यात व्यापार की मात्रा में वृद्धि दरें उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों की आयात और निर्यात व्यापार की मात्रा में वृद्धि दरों की तुलना में अधिक अनुमानित किया गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जिसमें यूरो क्षेत्र में संकट के अंतिम समाधान के संबंध में शंकाएं, अमरिका में वित्तीय निकासी की गति के संबंध में शंकाएं, जापान में भूकंप के पश्चात् पुनर्निर्माण की गति में वृद्धि को बनाए रखने के मार्ग की चुनौतियां तथा चीन के साथ व्यापार में विखराव आना जो हालांकि समय के साथ परिवर्तनीय है, किंतु भारत सहित अन्य उभरती और विकसित हो रहीं अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) के व्यापार विकास पर प्रभाव डालती रही।

सारणी 7.1 : व्यापार मात्रा में वृद्धि संबंधी रूझान

(प्रतिशत में परिवर्तन)

			अनुमान	
	2011	2012	2013	2014
विश्व व्यापार की मात्रा (माल एवं सेवाएं)	**5.9**	**2.8**	**3.8**	**5.5**
आयात				
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	4.6	1.2	2.2	4.1
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	8.4	6.1	6.5	7.8
निर्यात				
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	5.6	2.1	2.8	4.5
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.6	3.6	5.5	6.9

स्रोत: आईएमएफ; डब्ल्यू ई ओ, अद्यतन जनवरी 2013

भारत का वाणिज्यिक व्यापार

7.4 भारत के वाणिज्यिक व्यापार में 2000 के दशक के दौरान काफी तेजी से वृद्धि हुई तथा यह 2000-01 में 94.1 बिलयन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010-11 में 620.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2011-12 में और आगे बढ़कर 793.8 बिलियन अमेरिका डालर हो गया। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी 2000 के क्रमश: 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में क्रमश: 1.7 प्रतिशत हो गयी। निर्यातक और आयातक देशों में भारत का स्थान वर्ष 2000 में क्रमश: 31 और 26 था जो 2011 में क्रमश: 19 और 12 हो गया। हालांकि, अनंतिम अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार 2004-05 में 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 43.2 प्रतिशत हो गया किंतु जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के 28 वाणिज्यिक निर्यात उसी अवधि के दौरान 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया।

भारत के निर्यात में वृद्धि

7.5 वर्ष 2008 में आई वैश्विक मंदी के पश्चात् सरकार द्वारा निर्यात में सहायता के लिए किए गए उपायों से प्रेरित होकर और साथ ही निम्न आधार प्रभाव के कारण 2010-11 में निर्यात में वृद्धि स्वतंत्रता के बाद से 40.5 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि 2011-12 में यह घट कर 21.3 प्रतिशत हो गई किंतु अभी भी यह 20 प्रतिशत से अधिक और 2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान ये 20.3 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से उच्च स्तर पर थी। जुलाई 2011 में 56.5 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि दर दर्ज करने के बाद नवंबर 2011 में उभर रही वैश्विक स्थिति के परिणाम स्वरूप नवंबर 2011 में निर्यात वृद्धि घटने लगी और अचानक घट कर एकल अंक के स्तर पर पहुंच गई और तत्पश्चात् मार्च 2012 से यह शून्य से नीचे के ऋणात्मक आंकड़ों में पहुंच गई। 2012-13 में मासिक निर्यात वृद्धि अप्रैल 2012 में हुई मामूली घनात्मक वृद्धि को छोड़कर शेष अवधियों में ऋणात्मक स्तर पर रही। 2012-13 के तीन महीनों के दौरान वर्षानुवर्ष निर्यात में दोहरे अंकों की गिरावट हुई तथा जुलाई 2012 में दर्ज की गई -15.1 प्रतिशत की गिरावट सबसे अधिक थी। जनवरी 2013 में 0.8 प्रतिशत की मामूली घनात्मक वृद्धि थी।

निर्यात वृद्धि और विनिमय दर परिवर्तन

7.6 डॉलर मूल्य में निर्यात वृद्धि 2012-13 (अप्रैल-जनवरी) में -4.9 प्रतिशत के स्तर पर ऋणात्मक थी जबकि 2011-12 (पूर्ण वर्ष) के दौरान 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। रुपये मूल्य में यह आंकड़ा 9.1 प्रतिशत अर्थात् धनात्मक था हालांकि इस संदर्भ में भी 2011-12 (पूर्ण वर्ष) के दौरान के 28.3 प्रतिशत के स्तर से गिरावट आई थी।

7.7 2000 और 2011 दशकों में भारत की निर्यात वृद्धि वैश्विक निर्यात वृद्धि से लगभग अधिक रहनी जारी रही। यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत की निर्यात वृद्धि दर विनिमय दर या विश्व विकास/व्यापार की दर पर निर्भर है। भारत की निर्यात वृद्धि और विश्व निर्यात वृद्धि के बीच काफी अनुरूपता है। (चित्र 7.1 और बाक्स 7.1)। भारत की निर्यात वृद्धि 2000 के दशक में और वर्ष 2011 में भी निरंतर विश्व निर्यात में हुई वृद्धि से अधिक स्तर पर रही है। यह वर्ष 2009 में स्पष्टत: दृष्टिगोचर होता है जबकि विश्व निर्यात और भारत के निर्यात दोनो में भारी गिरावट हुई थी। वास्तविक प्रभावी वनिमय दर (आरईईआर) और भारत की निर्यात वृद्धि में परिवर्तनों के बीच संबंध विश्व व्यापार के बीच के संबंध के समान ही सुस्पष्ट नहीं हैं।

चित्र 7.1: विश्व और भारत की निर्यात वृद्धि और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) परिवर्तन

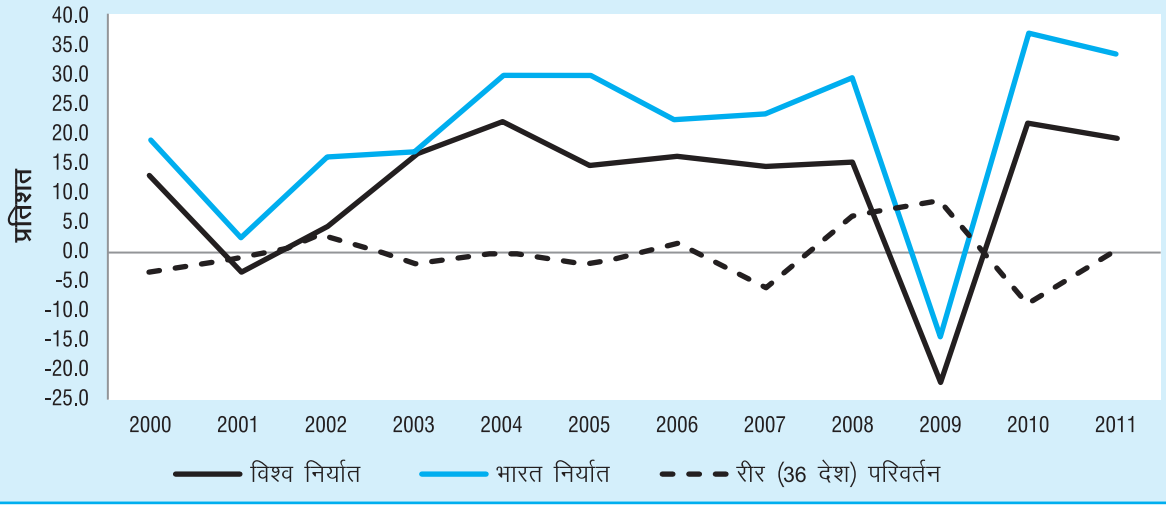

बॉक्स 7.1 : निर्यात में हाल के वर्षों में आई मंदी की किस हद तक बाह्य कारकों द्वारा व्याख्या की जाती है?

गत कुछ तिमाहियों के दौरान भारत में निर्यात वृद्धि में पर्याप्त मंदी आई है। व्यय पक्ष से जीडीपी आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक निर्यात के वर्षानुवर्ष वृद्धि 2011 की पहली तिमाही के 36% के उच्चतम स्तर से घटकर 2012 की तीसरी तिमाही में 4% हो गई है। वाणिज्यिक निर्यात में और अधिक मंदी आई है जो 2011 की पहली तिमाही की 34% से वर्षानुवर्ष घटकर 2012 की तीसरी तिमाही में -6% हो गई (वास्तविक संदर्भों में निर्यात सृजन हेतु यूएस सीपीआई द्वारा अपस्फीति बीओपी पर आधारित)। महत्व की बात यह है कि भारत के लिए मंदी का परिणाम संपूर्ण विश्व और साथ ही चीन के लिए भी अधिक सुस्पष्ट रहा है।

निर्यात में वृद्धिः भारत (वर्षानुवर्ष)

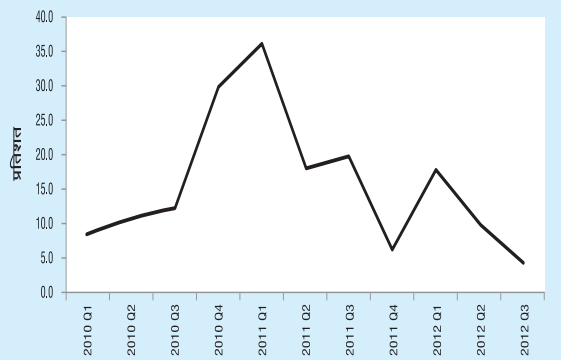

पण्य निर्यात की वृद्धि दर (वर्षानुवर्ष)

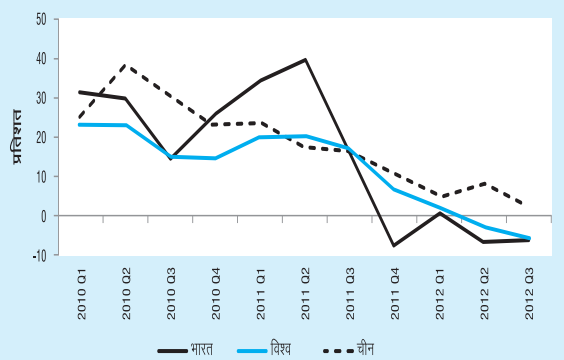

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी संबंधी सीईआईसी और आईएमएफ निर्देश।

टिप्पणी: बायां पैनल: वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से संबंधित आंकड़े जीडीपी व्यय से लिए गए हैं, 2004-05 के मूल्यों पर मापित। रायां पैनल: वास्तविक निर्यात से संबंधित आंकड़े यूएस सीपीआई और यूएस डॉलर में निर्यात अपस्फीति द्वारा ज्ञात किए गए हैं।

निर्यात वृद्धि में कमी आने के कम से कम दो कारण हैं: (प) बाह्य कारक या भागीदार देश की आय; (पप) विनिमय दर में परिवर्तन। भागीदार देशों की जीडीपी वृद्धि दर में भी काफी कमी आई है। वर्ष 2010 की पहली तिमाही की 6% से भी अधिक दर से वर्षानुवर्ष घटकर 2012 की तीसरी तिमाही में 1% से भी कम हो गई) इसका भारत की निर्यात वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर भार त के संदर्भ में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में कमी आई है जो निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव का परिणाम है।

व्यापार भारित भारत के भागीदारों की देशीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (वर्षानुवर्ष)

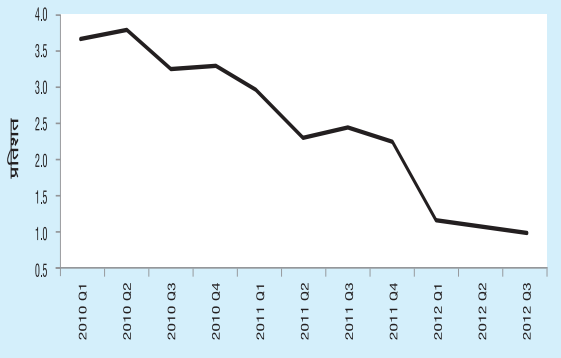

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) 2005 = 100

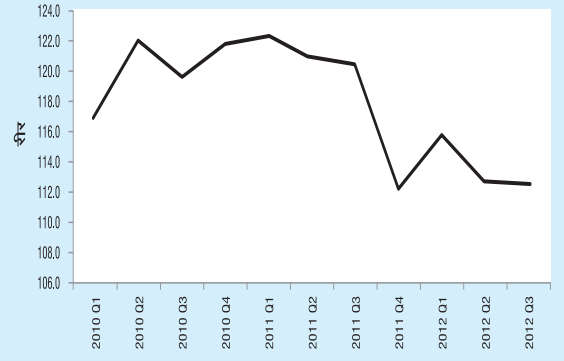

भागीदार देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि श्रृंखला भारत के शीर्षस्थ व्यापारित भागीदारों (तेल निर्यातकों को छोड़कर) के लिए तिमाही जीडीपी की वर्षानुवर्ष वृद्धि का भारित औसत हैं। आरईईआर श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सूचना नोटिस प्रणाली (आईएनएस) से प्राप्त की गई है। औरईईआर सूचक सीपीआई आधारित हैं तथा गृह देश में उपभोक्ता मूलों के स्तर के भारित ज्यामितीय औसत जो अपने व्यापार भागीदारों के संगत होते हैं, के एक भारित ज्यामितीय औसत के रूप में परिलक्षित किए जाते हैं। भारित मानों का सभी 184 आईएमएफ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के आधार पर परिकलन किया जाता है।

निर्यात वृद्धि में हुई कमी को समाप्त करने के लिए बाह्य मांग और विनिमय दरों के संबंध में निर्यात की मूल्य सापेक्षता का परिकलन किया जाना है। इसके लिए 1991-2009 से आंकड़ों का प्रयोग करके वास्तविक प्रभावी विनिमय दरों तथा भारत के व्यापारिक भागीदारों के व्यापार-भारित वास्तविक जीडीपी पर वास्तविक निर्यात (1895 मिलियन अमेरीकी डालर) में अत्यधिक कमी हुई है। सभी चार वस्तुओं के पहलें अंतरों के लघु गणक (लॉग) में विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिमानित विनिर्दिष्टयों से प्राप्त अनुमानों से यह ज्ञात होता है कि व्यापार भारित भागीदार देश के वास्तविक जीडीपी में एक प्रतिशत अंक वृद्धि भारत की निर्यात वृद्धि से

(जारी....)

बॉक्स 7.1 : निर्यात में हाल के वर्षों में आई मंदी की किस हद तक बाह्य कारकों द्वारा व्याख्या की जाती है? (जारी....)

2.5 प्रतिशत अंक वृद्धि से संबद्ध है जबकि भारत की निर्यात वृद्धि पर विनिमय दर परिवर्तन का सांख्यिकीय दृष्टि से कोई उल्लेख प्राप्त नहीं पाया जाता। ये अनुमान अजीज तथा शेनॉय (2020) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2012) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुरूप है।

यह ज्ञात करने के लिए कि भारत द्वारा निर्यात में कमी का कितना अंश बाह्य मांग में कमी के कारण है, भागीदार देश के जीडीपी के संबंध में निर्यात की मूल्य सापेक्षता का प्रयोग किया जाता है। औसतन 2011-12 और 2012-13 (पहली दो तिमाहियों में) के बीच निर्यात वृद्धि में 8.3 प्रतिशत की कमी आई है। 2.5 की प्रत्यास्थता का प्रयोग करके 5.2 प्रतिशत गिरावट के कारण भागीदार देश के जीडीपी में कमी से स्पष्ट किया जा सकता है अर्थात निर्यात में लगभग दो तिहाई कमी का कारण बाह्य कारकों को ठहराया जा सकता है। चूंकि इस अवधि के दौरान वास्तविक विनिमय दर में कमी आई है, अत: सांख्यिकीय दृष्टि से पर्याप्त प्रभाव ज्ञात किए जाने की परिस्थिति में भी निर्यात में कमी का कारण विनिमय दर परिवर्तनों को नहीं ठहराया जा सकता। (सारणी-1)

सारणी 1 : वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में गिरावट

	भागीदारी जीडीपी वृद्धि (%में)	वृद्धि भारत
औसत 2011-12	3.1	15.5
औसत 2012-13	1.0	7.2
कमी (प्रतिशत अंकों में)	2.1	8.3

मूल्य सापेक्षता 2.5; स्पष्ट 5.2; अवशिष्ट 3.1; स्पष्ट प्रतिशतांक 62

स्रोत: श्री रोहित लांबा और डा॰ प्राची मिश्रा द्वारा अध्ययन

व्यापार की मात्रा और एकांश मान

7.8 2010-11 में रुपए के संचयी में अत्युच्च निर्यात वृद्धि दर पूर्व वर्ष के अत्यधिक निम्न आधार से मात्रा और एकांश मूल सूचकांकों दोनों में उच्च वृद्धि होने के कारण है (सारणी 7.2) जबकि ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं को छोड़कर अखाद्य कच्ची सामग्री के कारण यूनिट मूल्यों में उच्च वृद्धि हुई, वहीं मशीन और परिवहन उपस्करों, खनिज ईंधनों, स्नेहकों और संबंधित समग्रियों तथा विनिर्मित वस्तुओं जिन्हें मुख्यत: पदार्थ और खाद्य सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई। 2011-12 में रुपये के संदर्भ में 28.3 प्रतिशत निर्यात में सूचकांक में 8.9 प्रतिशत उच्च वृद्धि के कारण हुई है जबकि यूनिट मूल्य सूचकांक में उच्च वृद्धि रासायनिक और संबद्ध उत्पादों में वृद्धि (41.2 प्रतिशत) ईंधन के अतिरिक्त गैर खाद्य कच्ची सामग्रियों

सारणी 7.2 : व्यापार मात्रा में वृद्धि संबंधी रूझान

(प्रतिशत में परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				आयात-निर्यात स्थिति	
	रुपए में	अमरीकी डालर में	परिमाण	यूनिट मूल्य	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	निवल	आय
2001-2	2.7	-0.6	0.8	1.0	6.2	2.9	4.0	2.8	-2.1	-1.7
2002-3	22.1	20.3	19.0	2.9	21.2	19.4	5.8	14.3	-9.8	7.8
2003-4	15.0	21.1	7.3	7.5	20.8	27.3	17.4	3.1	3.6	10.4
2004-5	27.9	30.8	11.2	14.9	39.5	42.7	17.2	18.9	-3.5	8.0
2005-6	21.6	23.4	15.1	6.1	31.8	33.8	16.0	14.0	-6.0	8.1
2006-7	25.3	22.6	10.2	13.7	27.3	24.5	9.8	15.1	-1.3	8.7
2007-8	14.7	29.0	7.9	5.1	20.4	35.5	14.1	1.9	2.6	10.9
2008-9	28.2	13.6	9.0	16.9	35.8	20.7	20.2	13.8	2.5	11.3
2009-10	0.6	-3.5	-1.1	1.0	-0.8	-5.0	9.9	-10.0	12.3	11.1
2010-11	35.2	40.5	15.2	13.8	23.4	28.2	8.0	13.0	1.1	16.7
2011-12	28.3	21.3	8.9	20.2	39.3	32.3	-20.9	74.9	-27.2	-20.7
2012-13[क]	9.1	-4.9	-	-	14.5	0.01	-	-	-	-

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डीजीसीआईएण्डएस) कोलकाता के आंकड़ों से संगणित। [क]: अप्रैल-दिसम्बर 2012
टिप्पणी : निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं यूनिट मूल्य सूचकांक नए आधार (1999-2000=100) के साथ हैं।

(41 प्रतिशत) तथा खनिज ईंधन और संबंधित सामग्री (36 प्रतिशत) के कारण है, निर्यात के परिणाम सूचकांक में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य एवं खाद्य वस्तुओं (35.9 प्रतिशत) मशीनरी एवं परिवहन उपकरण (28 प्रतिशत) और विविध विनिर्मित वस्तुओं (16.8 प्रतिशत) के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई। देशवार निर्यात परिमाण सूचकांक ब्यौरे से यह ज्ञात होता है कि 2011-12 में इस सूचकांक में उच्च वृद्धि निर्यात मात्रा में वृद्धि जापान (26.8 प्रतिशत), बेल्जियम (26 प्रतिशत), बांग्लादेश (20.9 प्रतिशत) और यूके (17 प्रतिशत) के कारण हुई है।

7.9 सामान्य मान्यता के विरुद्ध, वर्ष 2011-12 में उच्च आयात वृद्धि (रुपये के संदर्भ में) मात्रा में वृद्धि होने के कारण नहीं बल्कि यूनिट मूल्य उच्च वृद्धि (74.9 प्रतिशत) के कारण हुई तथा 2011-12 में आयात की मात्रा में ऋणात्मक वृद्धि भी हुई जिसका आंकड़ा -20.9 प्रतिशत है। आयात का यूनिट मूल्य सूचकांक 2011-12 में असामान्य रूप से 74.9 प्रतिशत की उच्च वृद्धि को दर्शाता है जो मुख्य रूप से उच्च भारित मदों मशीनरी तथा परिवहन उपकरण (169.2 प्रतिशत) के यूनिट मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है; तथा खनिज ईंधन, स्नेहक तथा संबंधित पदार्थों (28.9 प्रतिशत) के मूल्यों में वृद्धि अपरिष्कृत पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि के कारण हुई है। आयात की मात्रा में उच्च ऋणात्मक वृद्धि मुख्य रूप से मशीनों तथा परिवहन उपकरण की मात्रा में कमी (-52 प्रतिशत) तथा मुख्य रूप से मेटेरियल में वर्गीकृत विनिर्मित वस्तुओं के आयात में कमी (-7.9 प्रतिशत) के कारण है।

7.10 2011-12 में व्यापार की निवल वस्तु विनिमय (अदला-बदली) जो आयात के यूनिट मूल्य सूचकांक के अनुपात के रूप में निर्यात के यूनिट मूल्य सूचकांक की माप करता है, आयात के यूनिट मूल्य सूचकांक में उच्च वृद्धि के कारण -27.2 प्रतिशत की कमी को प्रदर्शित करता है जबकि निर्यात के यूनिट मूल्य सूचकांक में वृद्धि कम रही। व्यापार का आय मद (घट-बढ़) जो आयात की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, 2001-02 के बाद पहली बार 20.7 प्रतिशत कम हुयी जो भारत के लिए अत्यधिक प्रतिकूल व्यापार स्थिति को सूचित करता है (चित्र 7.2) 2001-02 में यह गिरावट काफी कम रही तथा सूचक के संगत संघटकों में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

भारत और ईडीई का निर्यात निष्पादन

7.11 18 ट्रिलियन अमरीकी डालर के विश्व निर्यात में चुनिंदा उभरते हुए तथा विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों (ईडीई) के हिस्से में में 2000 के बाद 41 प्रतिशत की एक बड़ी वृद्धि हुई है तथा इसकी हिस्सेदारी में 15.6 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। यदि चार नए औद्योगिकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं नामश: सिंगापुर,होंगकांग, ताइवान और कोरिया गणराज्य जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत वगीकृत कर दिया है भी इसमें शामिल होते तो यह हिस्सा 50 प्रतिशत हो जाता। चीन का निष्पादन काफी शानदार रहा है तथा 2000 और 2011 के बीच विश्व निर्यात में इसकी हिस्सेदारी में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान ईडीई हिस्सेदारी की कुल वृद्धि में इसका हिस्सा 42.2 प्रतिशत है जबकि भारत के हिस्से में 1 प्रतिशत अंक वृद्धि होने से कुल वृद्धि में इसकी भागीदारी केवल 6.5 प्रतिशत है। तथापि, 2011 में चीन की निर्यात वृद्धि दर 20.3 प्रतिशत थी जो भारत से काफी कम थी। भारत की 2010 में 37.3 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 2011 में निर्यात में 33.8 प्रतिशत वृद्धि दर विश्व में एक सर्वाधिक उच्च वृद्धि दर है।

7.12 विश्व वाणिज्यिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो 2009 से अत्यधिक तेजी से बढ़नी शुरु हुई और 2010 में 1.5 प्रतिशत तथा 2011 में 1.7 प्रतिशत हो गई। 2012 (जनवरी-अक्तूबर) में

चित्र 7.2: व्यापार की शर्तें

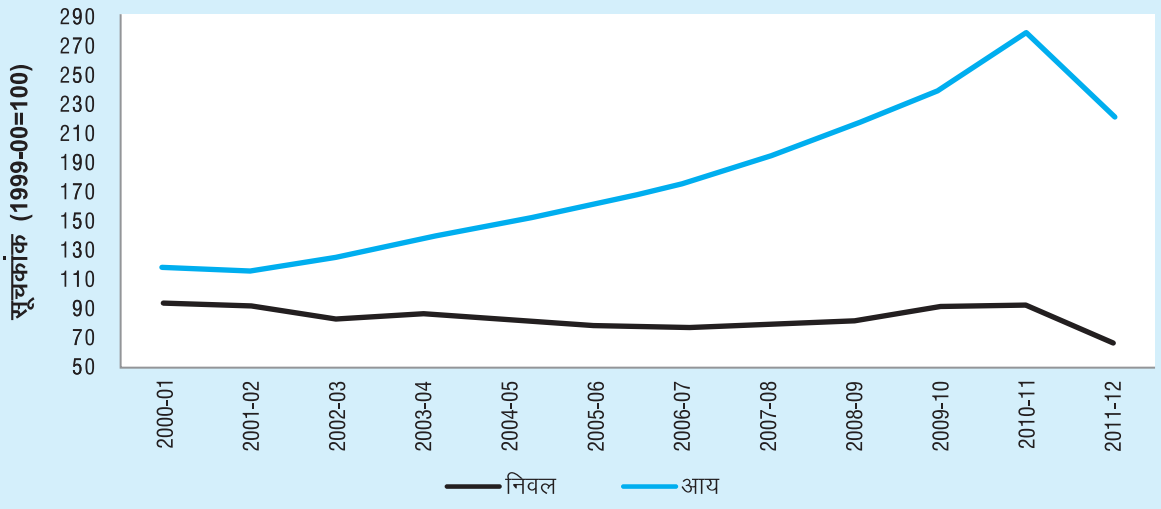

सारणी 7.3 : निर्यात वृद्धि और विश्व निर्यात में हिस्सेदारी: भारत एवं अन्य चुनिन्दा देश

	मूल्य बिलियन अमरीकी डालर 2011	सीएजीआर 2000-09	विकास दर % वार्षिक 2010	2011	2012 (जनवरी-अक्टू.)	विश्व निर्यात में हिस्सा (%) 2000	2010	2011	2012 (जनवरी-अक्टू.)	हिस्से में परिवर्तन 2011/2000
ईडीई	**7400**	**12.3**	**28.8**	**24.9**	**1.8**	**25.4**	**39.2**	**41.0**	**41.7**	**15.6**
जिनमें										
चीन	1899	19.1	31.3	20.3	7.9	3.9	10.4	10.5	11.2	6.6
रूस	522	12.5	32.0	30.4	3.1	1.7	2.7	2.9	2.9	1.2
मेक्सिको	350	3.6	29.8	17.3	7.0	2.6	2.0	1.9	2.1	-0.7
भारत	303	16.3	37.3	33.8	-5.1	0.7	1.5	1.7	1.6	1.0
मलेशिया	228	5.4	26.2	14.8	-0.6	1.5	1.3	1.3	1.3	-0.3
ब्राजील	256	12.0	32.0	26.8	-5.2	0.9	1.3	1.4	1.3	0.6
थाईलैंड	226	9.2	28.6	15.9	0.8	1.1	1.3	1.3	1.3	0.2
इंडोनेशिया	201	6.9	32.1	26.9	-6.2	1.0	1.0	1.1	1.0	0.1
दक्षिण अफ्रीका	97	8.5	30.7	18.5	-9.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1
एनआईएईस*										
कोरिया रिपब्लिक	557	8.6	29.0	19.3	-1.3	2.7	3.1	3.1	3.0	0.4
हांगकांग	429	5.2	22.5	9.9	1.4	3.2	2.6	2.4	2.4	-0.8
सिंगापुर	410	7.8	30.4	16.4	0.3	2.2	2.3	2.3	2.3	0.1
ताईवान	308	3.6	34.8	12.2	NA	2.3	1.8	1.7	उन	-0.6
विश्व	**18033**	**7.7**	**22.0**	**19.4**	**-0.2**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**-**

स्रोत : अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ जनवरी, 2013 से परिकलित
टिप्पणी : * नई औद्योगिकृत एशियाई अर्थव्यवस्था उन : उपलब्ध नहीं

यह मामूली घट कर 1.6 प्रतिशत हो गई जो मुख्यत: -5.1 प्रतिशत के अपेक्षाकृत ऋणात्मक निर्यात वृद्धि के कारण हुई जबकि विश्व निर्यात वृद्धि -0.2 प्रतिशत हुई (सारणी 7.3)। इसके विपरीत चीन की हिस्सेदारी 2012 (जनवरी-अक्तूबर) में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई जो 7.9 प्रतिशत के घनात्मक निर्यात वृद्धि का सूचक है।

7.13 भारत के कुछ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों के आयात और निर्यात से संबंधित नवीनतम मासिक वृद्धि दर निम्न या ऋणात्मक रही है (सारणी 7.4)। 2012 के अधिकांश महीनों के दौरान यूरोपीय यूनियन के देशों की आयात वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। अमरीका, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में गत दो या तीन महीनों में और चीन में दिसंबर 2012 में आयात वृद्धि में मामूली किंतु अस्थिर वृद्धि हुई है।

भारत के आयात में वृद्धि

7.14 पूर्व वर्ष में गिरावट से 2010-11 में उबरने के बाद भारत का वाणिज्यिक आयात 2011-12 में 32.3 प्रतिशत की दर से बढ़कर 489.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया

चित्र 7.3: पीओएल आयात

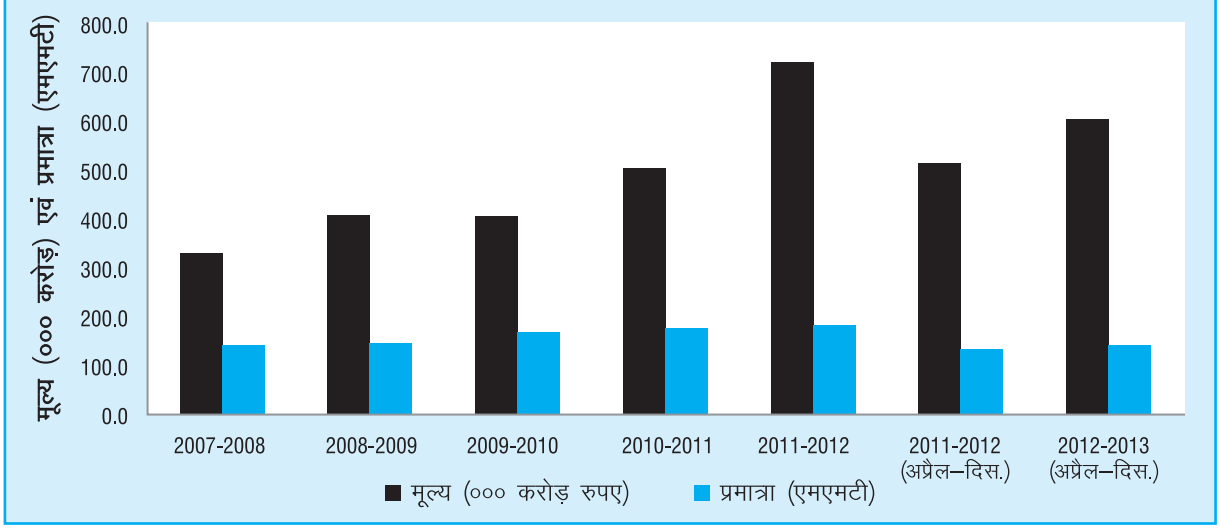

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित

बॉक्स 7.2 : सोने का आयात और नीतिगत उपाय

भारत विश्व में सोने का एक सबसे बड़ा आयातक देश है तथा वर्ष 2011-12 के दौरान भारत में सोने के आयात में मात्रा के संदर्भ में 11.2% तथा मूल्य के संदर्भ में 39.0% की वृद्धि हुई। भारत में सोना पीओएल के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ी आयात मद है तथा मूल्य के संदर्भ में 2011-12 के दौरान भारत द्वारा किए गए आयात में इसकी कुल हिस्सेदारी 11.3 थी। सोने के आयात में वृद्धि 2011-12 में भारत के उच्च व्यापार घाटे तथा सीएडी में योगदान करने वाला एक उपादान है तथा व्यापार घाटे में इसकी हिस्सेदारी 30% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ''भारत में सोने के आयात तथा एनबीएफसी द्वारा गोल्ड लोन से संबंधित मुद्दों'' का अध्ययन करने के लिए गठित किए गये कार्यदल के अपनी प्रारूप रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सोने के आयात में वर्ष 2011-12 में 39% के बजाय 24% (गत तीन वर्षों के दौरान विश्व द्वारा सोने की मांग में औसत वृद्धि) हो तो सीएडी में लगभग 6 बिलियन अमरीकी डालर की कमी आएगी तथा सीएडी-जीडीपी अनुपात 4.2% के 3.2% होगा विश्व भर में मुख्य रूप से चीन और भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की मांग के कारण सोने की मांग में वृद्धि हुई है। सोने के आयात के लिए प्रमुख स्रोत देशों में स्विटजरलैंड का नाम शामिल है जहां से 2011-12 के दौरान भारत द्वारा आपरिष्कृत सोने के कुल आयात के 52% का आयात किया गया (जिसके फलस्वरूप भारत के लिए प्रतिकूल द्विपक्षीय व्यापार संतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई), जिसके पश्चात् यूएई (17.6%), दक्षिण अफ्रीका (11.5%) का स्थान है। सोने के आयात में वृद्धि के अनेक कारण हैं।

सोने के लिए भारतीयों का प्रेम जग जाहिर है। भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है जहां सोने की खपत 2006 के 721.9 टन से बढ़कर 2011 में बढ़कर 933.4 टन तथा 2012 की पहली तीन तिमाहियों में 612 टन हो गयी जो 2011 में विश्व भर में सोने की कुल खपत का 27% तथा 2012 (पहली तीन तिमाहियों का योग) में 26.4% हो गई। खान मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में सोने का घरेलू उत्पादन मात्र 2.8 मीट्रिक टन होने का अनुमान है जिससे लगभग 0.3% मांग की ही पूर्ति हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप सोने का आयात अनिवार्य हो गया है। सोने का उपयोग व्यापार/निवेश के लिए भी किया जाता है। निवल खुदरा निवेश भारत में सोने की कुल खपत का 39.2% तथा मात्रा के संबंध में 2012 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 32.4% थी। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, हाल के वर्षों में सोने की मांग का एक प्रमुख घटक वैश्विक स्तर पर निवेश मांग में वृद्धि होना है। हाल के वर्षों में सोने के मूल्यों में वृद्धि भी भारत में सोने की मांग पर रोक नहीं लगा सकी है जिसका अर्थ यह है कि सोने में निवेश इसके मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी से प्रभावित नहीं होती। भारत विनिर्माण प्रयोजनों के लिए भी सोने का आयात करता है तथा इसका एक हिस्सा आभूषण के रूप में निर्यात करता है। भारत द्वारा मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषणों का जिन देशों को निर्यात किया जाता है उनमें यूएई (57.9%), हांक कांग (14.1%), तथा अमरीका (12.0) के नाम शामिल हैं।

सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव जो हाल के वर्षों में काफी अधिक रहा है, का भी देश द्वारा सोने के आयात मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। 2000 से 2012 की अवधि के दौरान सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में 16.2% सीएजीआर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में इनमें 23.4% की वृद्धि हुई हालांकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2012 की अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि घटकर 4.3% हो गयी। मूल्यों में यह कमी आने के बावजूद नवम्बर 2012 में सोने का मूल्य 1721 अमरीकी डालर प्रति ट्राय आन्स थी तथा वर्तमान में 1672.3 अमरीकी डालर प्रति ट्राय आन्स है (5 फरवरी 2013 के अनुसार) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, हाल की तिमाहियों में सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी आयी है जिससे कुछ लोगों को हानि और अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं। लगातार बिगड़ रही वैश्विक स्थिति के कारण भी एक सुरक्षित धातु के रूप में सोने की खरीद की जा रही है जिसके मूल्य में आगे और वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा उस पर लगने वाले शुल्क तथा करों के कारण भारत में सोने के मूल्यों पर स्वत: प्रभाव पड़ता है। सोने के मूल्यों में काफी वृद्धि से सकारात्मक मूल्य प्रत्याशा में वृद्धि हुई है जिससे हाल के वर्षों में सोने के आयात की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

सोने का आयात जो भारत के भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, के बढ़ते हुए रूख पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए और किए जा रहे हैं। 2012-13 के बजट में मानक सोने तथा प्लेटिनम पर आयात शुल्क 2% से बढ़कर 4% कर दिया गया तथा गैर मानक सोने पर आयात 5% बढ़ाकर 10% कर दिया 21 जनवरी, 2013 को सोना तथा प्लेटिनम पर आयात शुल्क 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि सोना विनिमय व्यापारित निधि (ईटीएफ) और सोना जमा स्कीम के बीच एक संबंध स्थापित किया जाए ताकि म्युचुअल फन्डों के पास सोना विनिमय व्यापारित निधि (ईटीएफ) के अन्तर्गत धारित सोने के एक हिस्से को अनफ्रिज या रिलीज किया जा सके तथा वे स्वर्ण जमा स्कीम के अन्तर्गत अपने पास मौजूद सोने को बैंकों में जमा करा सके। अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान सोने का आयात मूल्य 14.7% घटकर 38.02 विलियन अमरीकी डालर हो गया तथा इसके आयात की मात्रा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.8% की कमी आयी। 2012 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान सोने की कुल खपत में भी 23% की कमी आई। जबकि सोने की आपुर्ति को संगठित माध्यमों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है वहीं अनधिकृत माध्यमों के जरिए सोने के अन्तरवाह के संबंध में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्तत: सोने के आयात को कम करने का सबसे अच्छा एवं धारणीय उपाय यह है कि ऐसे सार्वजनिक वित्तीय निवेश अवसरों की पेशकश की जाए जिससे आकर्षक लाभ प्राप्त हो सकते हो। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा स्फीति में कमी लायी जाए और साथ ही ऐसे अवसरों का रेंज विस्तृत किया जाए जिनका निवेशक आसानी से उपयोग कर सके।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सिस बैंक तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की रिपोर्टों तथा आंकड़ों से संकलित

(देखें परिशिष्ट सारणी 7.1(ख) यह पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) के आयात में 46.2 प्रतिशत तथा अन्य उत्पादों के आयात में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुआ। पेट्रोलियम तेल और स्नेहक के आयात (जिसकी भारत के कुल आयात में 31.7 प्रतिशत भागीदारी है) में उच्च वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 2011-12 में भारत के अपरिष्कृत तेल आयात में आयात मूल्य में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि होना है जबकि 2010-11 में इसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चित्र 7.3)।

7.15 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों के आयात की मात्रा में वृद्धि दर 2009-10 में 14.9 प्रतिशत थी जो घटकर 2010-11 में 3.7 प्रतिशत और 2011-12 में 3.5 प्रतिशत हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य (ब्रेन्ट) जी जुलाई 2008 में 132.47 अमेरीकी डॉलर/बिलियन बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, वैश्विक मंदी के कारण दिसंबर 2008 तक तेजी से गिरकर 40.61 अमेरीकी डॉलर/बिलियन बैरल पर पहुंच गया। 2009 से तेल के मुल्य में वृद्धि हो रही है जिसमें बीच-बीच में मामूली कमी आती है। इस प्रकार मार्च 2002 में दूसरा मूल्य 125.33 अमेरीकी डॉलर/बिलियन बैरल ऊपर तत्पश्चात के महीनों में इसमें मामूली गिरावट आती रही। वर्तमान में ब्रेन्ट तेल मूल्य 110 अमेरीकी डॉलर बिलियन बैरल के आस-पास पहुंच गया है।

7.16 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सोना और चांदी के आयात (जिनका भारत के कुल आयात में 12.6% हिस्सेदारी है) में 44.5% की वृद्धि हुई। सोना और चांदी के कुल आयात में अकेले सोने का आयात ही कुल आयात का 91.7% था। 2011-12 में सोने के आयात में मूल्य संदर्भ में 38.8% की तथा मात्रा के संदर्भ में 11.2% की वृद्धि हुई। 2011-12 में पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) से भिन्न अन्य पदार्थों के आयात में 23.3% की वृद्धि हुई जबकि 2010-11 में 29% वृद्धि हुई थी।

7.17 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 406.9 विलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात किया गया और इस प्रकार आयात में -0.1% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13 (अप्रैल-दिम्बर) अवधि के दौरान पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक का आयात 125.2 विलियन अमरीकी डालर मूल्य का किया गया और इस प्रकार इसमें 12.8% की वृद्धि हुई। गैर पीओएन पदार्थों का आयात 239.8 विलियन अमरीकी डालर मूल्य का किया गया जो 5.1% की कमी को सूचित करता है तथा सोने एवं चांदी का आयात 39.3 विलियन अमरीकी डालर का किया गया तथा इसमें 14.7% की गिरावट दर्ज की गयी। गैर पीओएल तथा गैर-बुलियन पदार्थों का आयात जो मूल रूप से औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का आयात तथा निर्यात हेतु आवश्यक आयात को प्रतिबिम्बित करता है, में 3.0% की कमी आई।

व्यापार घाटा

7.18 व्यापार घाटा (कस्टम आधार) वर्ष 2010-11 के 118.6 विलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 184.6 विलियन अमरीकी डालर के शिखर पर पहुंच गया जो 1950.1 के बाद से 55.6% की उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है। विशेषकर पीओएल वस्तुओं के आयात में उच्च मूल्य तथा उच्च मात्रा में सोना तथा चांदी के आयात के कारण निर्यात में मामूली वृद्धि तथा आयात में उच्च वृद्धि दर्ज की गयी जिसके फलस्वरूप 1950.1 के बाद से भारत को सर्वाधिक व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वर्तमान उच्च लेखा घाटा 4.2% उठाना पड़ा (बॉक्स 7.2 भी देंखे)

7.19 व्यापार घाटे की मात्रा 2012-13 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 167.2 बिलियन अमरीकी डालर थी जो 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में हुए 154.9 बिलियन अमरीकी डालर घाटे की तुलना में 7.9% अधिक था। जबकि 2011-12 में पीओएल आयात में 46.2% की वृद्धि हुई वहीं पीओएल के निर्यात में वृद्धि अपेक्षाकृत 34% कम हुई जो पीओएल के निर्यात की मात्रा में 3.8% की कम वृद्धि के कारण थी जिसके फलस्वरूप निवल पीओएल आयात 2011-12 में बढ़कर 99.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2012-13 (अप्रैल-नबम्वर) में हालांकि पीओएल आयात में वृद्धि घटकर 11.7% हुई किन्तु पीओएल के निर्यात में वृद्धि ऋणात्मक -7.3% हुई जो भी पीओएल निर्यात की मात्रा में -0.9% की कमी के कारण हुई इसके परिणामस्वरूप कुल आयात में पीओएल आयात की हिस्सेदारी बढ़कर 2012-13 (अप्रैल-नबम्वर) के दौरान 23.5% हो गई जबकि 2011-12 (पूरा वर्ष) के दौरान यह आंकड़ा 20.3% का था।

व्यापार संयोजन

निर्यात संयोजन

7.20 भारत के निर्यात संयोजन में वर्षानुवर्ष परिवर्तन होता रहा है। जबकि इन वर्षों के दौरान भारत के निर्यात में प्राथमिक उत्पादों की हिस्सेदारी 2000-01 के 16% से घटकर 2012-13 (अप्रैल-नबम्वर) में एक बार फिर से 16% के स्तर पर पहुंच गयी जो मुख्य रूप से चावल और ग्वार गोंद भोजन जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के कारण हुआ है। विनिर्मित पदार्थों की हिस्सेदारी 2000-01 में 78.8% थी जो काफी अधिक गिरकर 2011-12 में 66.1% के स्तर पर पहुंच गयी तथा 2012-13 (अप्रैल-नबम्वर) में और अधिक गिरकर 64.5% के स्तर पर पहुंच गयी जो मुख्य रूप से परमपरागत वस्तुओं जैसे कि टैक्सटाइल, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्माण की हिस्सेदारी में कमी आयी यद्यपि इंजीनियरी वस्तुओं तथा रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। रत्न तथा आभूषण की हिस्सेदारी में मामूली कमी आयी। पेट्रोलियम, अपरिष्कृत तथा उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी जिसमें परिष्कृत मदें भी शामिल है, 2000-1 के 4.3% से बढ़कर 2011-12 में 18.3% और 2012-13 (अप्रैल-नबंवर) में 18.6% हो गई।

7.21 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की प्रमुख वस्तुओं के लक्ष्यवार निर्यात 2009-10 से लेकर 2012-13 (अप्रैल-नबंवर) के दौरान

सारणी 7.4 : प्रमुख बाजारों के अनुसार निर्यात की संरचना

	प्रतिशत हिस्सा						वृद्धि दर*				
	2000-01	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)
I. प्राथमिक उत्पाद											
विश्व	16.0	14.9	13.2	15.2	13.3	16.0	3.8	23.9	39.8	37.2	11.2
अमरीका	9.4	6.8	8.0	14.5	11.9	21.3	-13.5	52.8	149.5	123.7	101.6
ई.यू.	13.1	8.6	8.2	9.7	9.0	9.9	-5.7	22.2	33.8	38.3	-2.0
चीन	45.2	65.7	51.6	55.2	49.5	38.4	26.9	4.7	24.8	7.0	-42.1
अन्य	18.9	13.1	11.7	13.1	11.7	14.9	-1.7	31.7	35.7	41.9	17.5
(क) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद											
विश्व	14.0	10.0	9.7	12.4	10.7	14.0	1.1	36.1	53.9	60.8	21.1
अमरीका	9.0	5.8	7.1	13.7	11.0	20.4	-12.1	58.7	165.7	139.3	107.3
ईयू	11.9	7.1	7.1	8.1	7.6	8.7	-6.4	27.7	30.4	37.9	1.3
चीन	18.9	14.8	16.8	26.5	20.4	17.8	122.8	50.6	84.2	79.1	-35.0
अन्य	16.8	11.3	10.2	12.0	10.7	13.8	-3.3	33.8	41.9	54.2	18.9
(ख) अयस्क एवं खनिज											
विश्व	2.0	4.9	3.4	2.8	2.6	2.0	9.9	-1.3	-0.4	-14.3	-29.6
अमरीका	0.4	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	-21.1	18.5	24.4	22.0	29.2
ईयू	1.3	1.5	1.2	1.6	1.4	1.2	-2.5	-3.5	54.6	40.7	-20.4
चीन	26.3	50.9	34.8	28.7	29.1	20.6	12.8	-8.7	-3.7	-16.6	-47.2
अन्य	2.2	1.8	1.5	1.1	1.0	1.1	9.6	18.6	-7.4	-23.7	1.9
II विनिर्मित वस्तुएं											
विश्व	78.8	67.2	69.0	66.1	66.9	64.5	-5.9	44.2	16.2	27.7	-10.4
अमरीका	90.6	89.1	87.4	81.4	83.3	74.2	-8.7	27.0	27.9	35.2	-0.2
ईयू	86.8	73.2	72.1	74.9	73.9	72.6	-15.4	25.8	18.6	34.4	-12.8
चीन	54.6	32.2	42.4	39.2	42.3	58.0	29.5	75.4	7.8	4.3	2.3
अन्य	71.4	65.1	67.8	63.5	64.4	60.8	-2.5	53.4	13.6	25.7	-12.6
(क) आरएमजी सहित कपड़ा											
विश्व	23.6	10.5	9.1	8.7	8.6	8.7	-1.2	21.3	16.9	29.1	-6.4
अमरीका	27.2	18.4	17.1	14.1	13.7	12.0	-7.6	20.2	13.0	19.2	-1.7
ईयू	29.2	18.5	16.3	16.3	15.7	14.4	-6.7	12.1	14.6	36.6	-18.7
चीन	9.3	1.8	2.8	4.1	3.7	8.6	47.0	104.2	68.5	51.4	73.6
अन्य	20.2	7.4	6.4	6.2	6.3	6.5	6.2	27.1	17.9	27.3	-4.0
(ख) रत्न एवं आभूषण											
विश्व	16.6	16.2	16.1	14.7	14.9	15.4	3.7	39.6	10.8	38.6	-4.0
अमरीका	29.3	24.2	20.8	19.5	22.3	18.0	2.8	11.7	28.5	52.7	-9.4
ईयू	11.5	6.7	6.8	9.2	9.2	7.1	-26.2	31.4	52.9	90.8	-31.5
चीन	0.0	3.8	0.5	0.7	0.7	0.7	-41.4	-81.0	42.8	25.0	-25.5
अन्य	14.4	19.2	19.5	16.6	16.4	18.0	10.7	49.1	3.6	30.5	1.5
(ग) इंजीनियरिंग वस्तुएं											
विश्व	15.7	18.2	19.8	19.2	19.2	19.3	-18.7	53.0	17.3	15.8	-6.4
अमरीका	13.4	17.1	20.2	19.8	20.5	17.1	-33.9	53.0	34.5	37.9	-6.6
ईयू	14.0	20.8	20.9	21.0	20.8	21.5	-25.1	28.6	14.6	26.3	-8.4
चीन	9.9	12.4	25.8	18.8	20.7	24.4	63.6	177.9	-14.8	-21.3	-11.9
अन्य	17.5	18.2	18.9	18.6	18.4	18.9	-15.8	53.2	19.3	14.6	-5.2
(घ) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद											
विश्व	10.4	12.8	11.5	12.2	11.8	13.7	0.9	26.0	28.6	35.4	7.4
अमरीका	5.7	17.2	17.7	16.9	15.9	17.2	7.4	33.2	30.9	28.9	21.1
ईयू	9.7	12.5	12.8	14.1	13.6	15.1	-11.8	30.9	25.6	36.6	-1.2
चीन	15.5	10.2	9.4	11.1	12.1	15.5	40.8	23.3	37.7	48.5	-4.5
अन्य	12.4	12.4	10.4	10.9	10.6	12.4	1.7	22.9	28.2	35.6	8.0
(ड.) चमड़ा एवं चमड़े का उत्पाद											
विश्व	4.4	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	-5.5	16.3	22.6	36.0	-2.8
अमरीका	3.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	-17.8	17.4	26.6	29.3	20.8
ईयू	11.4	6.3	5.5	5.8	5.9	5.8	-2.1	12.6	20.2	39.7	-12.5
चीन	1.1	0.4	0.5	0.7	0.7	1.1	-2.2	55.5	65.2	74.3	12.9
अन्य	1.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	-9.9	24.8	24.2	26.4	12.8
(च) हथकरघा											
विश्व											
अमरीका	2.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-10.6	35.7	-12.9	-6.7	7.4
ईयू	6.0	1.5	1.6	1.2	1.2	1.3	-14.6	40.4	2.4	14.6	16.5
चीन	4.4	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	-7.5	8.4	-12.1	-3.8	-2.9
अन्य	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	106.9	-40.9	40.1	16.3	-2.4
III पेट्रोलियम, कच्चा तेल एवं उत्पाद	0.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	-13.1	80.1	-29.2	-27.9	8.5
कुल निर्यात											
विश्व	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-3.5	40.5	21.3	32.7	-7.0
अमरीका	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-7.6	29.5	37.4	43.9	12.2
ईयू	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-8.4	27.9	14.1	31.4	-11.2
चीन	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	24.2	33.3	16.8	12.4	-25.4
अन्य	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-3.4	47.2	21.3	33.3	-7.6

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस तथा अपनी स्वयं की गणनाएं। *वृद्धि दर अमरीकी डालर में

टिप्पणी: 1. आरएमजी का अर्थ है तैयार परिधान

2. किसी मद विशेष में हिस्से का अर्थ है उस देश को किए गए भारत के कुल निर्यातों में प्रत्येक देश का हिस्सा।

3. कुछ अवर्गीकृत मदों के कारण जोड़ संभवत: मेल न खाएं।

बाक्स 7.3 : बाजार बनाम उत्पाद विविधीकरण

भारत अमरीका और यूरोप से एशिया तथा अफ्रीका जैसे विकसित देशों से अपने निर्यात बाजारों के विविधीकरण में पूरी तरह सफल रहा है जिसने वर्ष 2008 के वैश्विक संकट तथा हालिया वैश्विक मंदी से कुछ हद तक उबरने में भारत की मदद की है

सारणी 1 : क्षेत्र-वार भारत के निर्यात का हिस्सा

		2000-1	2005-6	2011-12	2012-13 (अप्रैल-नवम्बर)
1)	यूरोप	25.9	24.2	19.0	18.7
2)	अफ्रीका	5.3	6.8	8.1	9.6
3)	अमरीका	24.7	20.7	16.4	19.5
4)	एशिया	37.4	46.9	50.0	50.4
5)	सीबाईएस एवं की बाल्टिक	2.3	1.2	1.0	1.3

स्रोतः डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

तथापि उत्पादों के विविधीकरण के संदर्भ में भारत द्वारा काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है

- वर्ष 2011 द्वारा चार अंकीय सुमेकित प्रणाली (एमएस) स्तर पर विश्व के शीर्ष 100 आयातों में भारत के पास शीर्ष 50 आयातों में केवल 6 मदें; 5 प्रतिशत या इससे अधिक के हिस्से वाली केवल 5 मदें; और 2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्से वाली 18 मदें (सारणी 2) 2010 के मुकाबले 2011 में सूची में शामिल होने वाले ताकि निर्यात वृद्धि (भारत) वाली 6 नई मदें तथा सूची से बाहर होने वाली 3 मदें हैं। नई मदें हैं ओषध उपयोग हेतु मिश्रित अथवा अवमिश्रित ओषद्यियां; लोहे और स्टील की अन्य वस्तुएं; पुरूषों अथवा लड़कों के सूट, परिधान; क्रूज शिप, एक्सकर्सन बोट फेरी बोट, कार्गो शिप, बार्गेस और इसी तरह के सामान, गन्ना अथवा चुकन्दर से बनी शक्कर तथा ठोस रसायनिक शुद्ध ईख की शक्कर; और मक्का।

सारणी 2 : चार अंकीय स्तर पर विश्व में शीर्ष 100 आयातों में 2 प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्से वाली भारत की निर्यात मदें

रैक# विश्व 2011	एच एस 4	मदें	2011 में वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा	2011 में वृद्धि दर भारत (निर्यात)	2011 में वृद्धि दर विश्व (आयात)
2	2710	पेट्रोलियम तेल और स्वलम्भीय खनिजों आदि से प्राप्त तेल	6.7	49.0	39.4
7	2004	औषध उपयोग के लिए मिश्रित अथवा अवमिश्रित उत्पादों से तैयार औषधी	2.1	36.0	5.7
11	2001	रोस्टेड आयरन पाइराइट सहित लौह अयस्क और सांकेन्द्रण	2.3	-32.3	37.8
14	7102	हीरे जिन पर काम हुआ हो या नहीं लेकिन जो जड़े या सेट न किए गए हो	23.8	44.7	14.7
34	7403	परिष्कृत तांबा और तांबा मिश्र धातु अपरिष्कृत	3.2	-53.7	12.2
39	8803	88.01 अथवा 88.02 शीर्ष सं. पर दी गई वस्तुओं के हिस्से	3.5	45.4	1.2
51	6403	रबड़ के बाहरी सोल वाले जूते चप्पल	3.1	23.0	9.2
52	6204	महिलाओं अथवा लड़कियों के सूट सीवन रहित पोशाकें, जैकिट, ब्लेजर आदि पोशाकें	4.9	34.8	9.2
55	7210	लौह अथवा गैर मिश्रित धातु स्टील के चपटे रोल किए गए उत्पाद	2.8	0.8	12.2
56	7113	बहुमूल्य धातु के आभूषण और इनके भाग	28.5	83.6	13.4
61	2902	चक्रीय हाइड्रोकार्बन	4.4	47.8	27.8
68	7326	लोहे अथवा स्टील की अन्य वस्तुएं	2.0	97.9	13.9
69	3902	पोपिलीन अथवा अन्य ओलिफिन्स आदि के पोलिमर्स	2.8	46.0	17.3
72	6203	पुरुषों अथवा लड़कों के सूट सीवन रहित, जैकिट, ब्लेजर ट्राउजर्स आदि	2.3	31.5	16.4
92	6109	टी शर्ट कमीज एवं अन्य बण्डी बुनी हुई अथवा क्रोशिए से बनी हुई	6.0	22.1	12.1
97	8901	क्रूज शिप एक्सकर्सन वोट, फेरी वोट, कार्गो शिप बार्गेज और इसी तरह के यान	2.2	40.0	-25.8
99	1701	गन्ना अथवा चुकन्दर से बनी शर्करा और रसायनिक शुद्धता वाली ठोस शर्करा	6.0	123.1	20.1
100	1005	मक्का	3.4	103.1	34.1

स्रोत : 9 जनवरी 2013 को तैयार यू एन कामट्रेड आकड़ों से संगठित
टिप्पणी : *रैंक शीर्ष 100 विश्व आयातों में

- भारत का चार अंकीय एम एस मदों में केवल दो मदों आभूषण और हीरे के मामले में वैश्विक आयात में बहुत बड़ा निर्यात का हिस्सा है। जहां भारत सारणी में दी गई अन्य 16 मदों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है विश्व के शीर्ष 100 आयातों में अन्य कई साधारण मदें है जिनकी बहुत अधिक मांग है और जिनमें भारत ने दक्षता हासिल कर ली है अधिकांश मदें तीन इज़ इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रीकल्स और इंजीनियरिंग के अन्तर्गत आती है और इनमें कुछ टेक्सटाइल मदे भी शामिल है। इस प्रकार वैश्विक आयात में भारत के निर्यात के हिस्सा में दृष्टिगोचर वृद्धि हुई है।

स्रोत : आन्तरिक अध्ययन। आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग

अमरीका तथा चीन को निर्यात के संयोजन में काफी परिवर्तन दिखाई देता है (सारणी-7.5)। भारत द्वारा अमरीका को निर्यात के मामले में प्राथमिक उत्पादों के निर्यात की भागीदारी 2009-10 में 6.8% थी जो 2012-13 (अप्रैल-नबंवर) में बढ़कर 21.3% हो गई जिसका मुख्य कारण कृषि तथा संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि होना है जबकि भारत द्वारा अमरीका को विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की मात्रा इसी अवधि के दौरान 89.1% से घटकर 74.2% हो गई। इस गिरावट का मुख्य कारण वस्तुओं तथा रत्न और आभूषणों के निर्यात की वृद्धि दर में कमी होना है। भारत द्वारा चीन को निर्यात के मामले में प्राथमिक उत्पादों की हिस्सेदारी 2009-10 के 65.7% से घटकर 2012-13 (अप्रैल-नबंवर) के दौरान 38.4% हो गई जिसका मुख्य कारण अयस्कों तथा खनिज पदार्थों की हिस्सेदारी तथा वृद्धि दर में कमी होना है। भारत द्वारा चीन को विनिर्मित पदार्थों के निर्यात की मात्रा इसी दौरान 32.2% स बढ़कर 58.0% हो गई जिसका कारण इंजीनियरी वस्तुओं, वस्त्रों तथा रसायनों और संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि होना है। भारत द्वारा यूरोपीय यूनियन के देशों को निर्यात के मामले में प्राथमिक उत्पादों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है तथा विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी में कमी आई है।

7.22 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में भारत के निर्यात में वृद्धि वर्ष 2009-10 के मुकाबले अधिक ऋणात्मक रही, वैश्विक मंदी का असर भारत के इस निर्यात निष्पादन पर देखा जा सकता है। 2009-10 की तुलना में हाल में छाई मंदी की अवधि के दौरान भारत से रूस इ यू चीन को किए गए निर्यात नकारात्मक रहे। जबकि रत्न और आभूषण के अलावा अधिकांश क्षेत्रों में अमरीका को किए गए निर्यात निष्पादन अपेक्षतया बेहतर रहे। वर्ष 2009-10 के मुकाबले वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में भारत का इ यू को किया गया टेक्सटाइल और तैयार कपड़े, रत्न एवं आभूषण तथा अयस्क और चीन को किए गए विनिर्माण इजीनियरी वस्तुएं, रसायन, रत्न एवं आभूषण तथा अयस्क का निर्यात निष्पादन खराब रहा। 2009-10 के मुकाबले 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में भारत की सभी बड़े बाजारों में की गई पीआएल निर्यात वृद्धि में गिरावट आई। इस प्रकार 2009-10 के मुकाबले यूरो क्षेत्र में व्याप्त संकट और चीन में छाई मंदी ने भारत के निर्यात को हालिया मंदी के दौर में ज्यादा प्रभावित किया।

निर्यात विविधता

7.23 वर्ष 2011 में भारत का दो अंकीय सुमेलित प्रणाली (एच एस) स्तर पर कुल 99 वस्तुओं में से 53 वस्तुओं में एक प्रतिशत या अधिक का वैश्विक निर्यात हिस्सा था। जहां भारत की बाजार विविधता में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं लेकिन इसके वस्तु समूह विविधता में बिल्कुल ऐसा नहीं है। (बाक्स 7.3 देखें)

आयात संरचना

7.24 हाल के वर्षों में भारत के आयात वस्तु समूह में कतिपय उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। पीओएल आयातों का हिस्सा 2010-11 में 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में (बहुत अधिक वृद्धि दर के साथ) 31.7 प्रतिशत तथा 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में 34.6 प्रतिशत हो गया। स्वर्ण और चांदी के आयातों का हिस्सा 44.5 प्रतिशत की अधिक आयात वृद्धि दर के साथ 2000-01 में 9.3 प्रतिशत से बढ़र 2011-12 में 12.6 प्रतिशत हो गया। तथापि स्वर्ण पर आयात शुल्क बढ़ाने जैसे नीतिगत उपायों के कारण 2012-13 में (अप्रैल-नवम्बर) में सोने एवं चांदी के आयातों में कमी आई इसमे -20.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के बाद इसके हिस्से में 10.5 प्रतिशत की गिरावट आई। मोती मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान मशीनों के आयात के हिस्से में भी 2011-12 में तीव्र गिरावट आई और यह -32.3 प्रतिशत की अधिक ऋणात्मक वृद्धि के साथ -13.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के बाद 6.1 प्रतिशत पर तथा 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) मे ओर गिरावट के बाद 4.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना पूंजीगत वस्तुओं के आयात के हिस्से से संबंधित है जो 2000-01 में 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 13.6 प्रतिशत और 2011-12 में फिर से बढ़कर 14.1 प्रतिशत हो गयी लेकिन इसके बाद 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में आयात के हिस्से में -6.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के बाद 11.9 प्रतिशत की गिरावट हुई। सभी पूंजीगत वस्तुओं में इलेक्ट्रीकल और मशीनी औजार, यातायात उपस्कर, परियोजना वस्तुएं और इलेक्ट्रिकल मशीनों के अलावा सभी प्रकार की मशीनों के आयात हिस्से में कमी आई जिससे औद्योगिक क्रियाकलापों में मंदी के संकेत दिखे। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं जिनमे उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स और पूंजीगत वस्तुएं दोनो शामिल हैं, के हिस्से में भी 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में गिरावट आई (सारणी 7.7 और परिशिष्ट सारणी 7.2 (ख) देखें।

व्यापार की दिशा

7.25 भारत के व्यापार में उल्लेखनीय बाजार विविधीकरण हुआ है। क्षेत्रवार जहां भारत से यूरोप और अमरीका को किए गए निर्यात में कमी आई वहीं भारत से एशिया और अफ्रीका को किए गए निर्यातों में वृद्धि हुई हैं (बोक्स 7.3 देखें)। हालाकि वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में भारत से अमरीका को किए गए निर्यात के हिस्से में 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एशिया के भीतर उत्तरपूर्वी एशिया (जिसमें चीन हांगकांग, जापान शामिल है। और एसियन (दक्षिण पूर्वी एशियाई शब्दों का संघ) का हिस्सा 2011-12 में क्रमश: 14.8 प्रतिशत तथा 12.0 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में 13.1 प्रतिशत तथा 10.3 प्रतिशत रह गया। पश्चिमी एशियाई जी सी सी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशें के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई इनका हिस्सा 2011-12 में 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में 17.7 प्रतिशत तक पहुंच गया।

7.26 वर्ष 2000-2001 के मुकाबले वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में भारत का यूरोप से किए गए आयात का हिस्सा 27.6 प्रतिशत से गिरकर 16.7 प्रतिशत रह गया, जबकि एशिया से भारत को किए गए आयात का हिस्सा 27.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर

सारणी 7.5 : भारत के आयातों की जिन्सवार संरचना

जिन्स समूह	प्रतिशत हिस्सा					सीएजीआर	वृद्धि दर (प्रतिशत)[क]			
	2000-01	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-नव.)	2012-13 (अप्रैल-नव.)	2000-01 to 2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-नव.)	2012-13 (अप्रैल-नव.)
I. खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद	**3.3**	**2.9**	**3.1**	**3.1**	**3.5**	**22.7**	**2.2**	**44.4**	**38.0**	**11.6**
जिनमें से										
1. अनाज	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	15.8	-34.2	-46.6	6.8
2. दलहन	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	38.3	-23.1	27.2	11.3	9.2
3. खाद्य तेल	2.6	1.8	2.1	2.1	2.5	17.2	19.0	57.7	55.3	18.0
II. ईंधन जिसमें से	**33.5**	**30.9**	**37.4**	**34.3**	**38.0**	**21.0**	**22.4**	**59.7**	**52.3**	**9.8**
4. पीओएल	31.3	28.7	31.7	30.7	34.6	21.0	21.6	46.2	50.6	11.7
III. उर्वरक	**1.3**	**1.9**	**2.4**	**2.3**	**2.2**	**29.0**	**4.8**	**72.1**	**32.2**	**-6.8**
IV. पूंजीगत वस्तुएं, जिनमें से	**10.5**	**13.6**	**14.1**	**12.6**	**11.9**	**26.1**	**19.2**	**36.9**	**25.6**	**-6.5**
5. इलेक्ट्रिकल एवं मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	5.9	7.0	7.2	6.7	6.3	24.4	24.0	35.8	28.2	-5.8
6. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	22.7	25.1	33.1	26.6	-5.5
7. परिवहन संबंधी उपकरण	1.4	3.1	3.0	2.5	2.3	36.4	-0.9	31.8	13.1	-8.3
V. अन्य, जिनमें से	**52.5**	**49.6**	**49.0**	**47.6**	**44.3**	**19.3**	**43.2**	**30.8**	**29.6**	**-7.6**
8. रसायन	5.9	5.2	5.1	5.0	5.1	19.5	29.6	31.8	24.3	1.1
9. मोती, कीमती पत्थर अर्द्ध कीमती पत्थर	9.7	9.3	6.1	6.1	4.1	14.0	116.9	-13.3	4.3	-32.3
10. सोना और चांदी	9.3	11.5	12.6	13.0	10.5	23.0	43.0	44.5	59.2	-20.4
11. इलेक्ट्रिक वस्तुएं	7.0	7.1	7.1	7.0	6.5	21.6	28.4	31.7	22.2	-7.7
कुल आयात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**21.5**	**28.2**	**32.3**	**36.2**	**-0.8**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित। [क] **अमरीकी डालर में वृद्धि दर**

61.1 प्रतिशत हो गया। भारत के आयातों में अमरीका का हिस्सा भी 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गया। भारत के व्यापार में इसके शीर्ष 15 व्यापारिक भागीदारों का 60 प्रतिशत हिस्सा है शेष तीन शीर्ष देशों के पास लगभग आधा हिस्सा है। जहां 2011-12 में शीर्ष 15 देशों की सूची में इरान और यूके नहीं थे, इराक और कुवेत इस सूची में जुड़े नए आगन्तुक देश है भारत के व्यापार की दिशा में एक दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों में अमरीका जो 2007-08 में पहले स्थान पर था बाद के वर्षों में पदावनत होकर तीसरे स्थान पर आ गया है। 2011-12 यूएई जो पहले स्थान पर था पदावनत होकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है और चीन 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में यूएई को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है 2012-13 के लिए अंतिम स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि अमरीका अपने हिस्से में लगभग एक प्रतिशत बिन्दु की बढत लिए चीन से महज इंच के फांसले पर है और चीन मामूली सा पीछे है।

7.27 वर्ष 2011-12 में 10 प्रतिशत के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के रूप में भारत का व्यापार घाटा विश्व में सर्वाधिक था। द्विपक्षीय व्यापार शेष को प्रतिविम्बित करने वाले निर्यात-आयात के अनुपात (सारणी 7.6) दर्शाते हैं कि 2011-12 में भारत का चार देशों नामश: संयुक्त अरब अमीरात सयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर और हांगकांग के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष था। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का व्यापार शेष मामूली से घाटे की स्थिति में चला गया बाद में संयुक्त राज्य अमरीका और हांगकांग के साथ इसमें सुधार हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति भारत का चीन और स्विट्जरलैण्ड के साथ बढ़ता व्यापार घाटा जो 2010-11 में क्रमश: 28 विलियन अमरीका डालर और 24.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 39.4 विलियन अमरीकी डालर तथा 31.3 विलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में चीन के साथ निर्यात-आयात अनुपात 2011-12 में 0.31 से आगे और क्रम होकर 0.23 रह गया।

सेवाओं का विश्व व्यापार

7.28 विश्व पण्य निर्यात की तरह, विश्व वाणिज्यिक सेवा व्यापार ने जो वर्ष 2008 के वैश्विक संकट से बुरी तरह प्रभावित

सारणी 7.6 : प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ भारत का व्यापार-हिस्सा तथा आयात-निर्यात अनुपात

क्र. सं.	देश	कुल व्यापार में हिस्सा					आयात-निर्यात अनुपात [क]				
		2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)
1	चीन	9.09	9.50	9.52	9.62	8.95	0.38	0.36	0.31	0.29	0.23
2	यू॰ए॰ई॰	9.31	10.72	9.03	8.99	9.74	1.23	1.03	1.00	0.98	0.92
3	अमरीका	7.82	7.30	7.46	7.29	8.23	1.15	1.26	1.42	1.42	1.51
4	सऊदी अरब	4.50	4.04	4.63	4.57	5.43	0.23	0.23	0.18	0.17	0.28
5	स्विटजरलैंड	3.27	4.11	4.22	4.30	3.50	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
6	सिंगापुर	3.01	2.73	3.21	3.30	2.53	1.18	1.38	1.96	1.85	1.75
7	जर्मनी	3.37	3.00	3.05	3.02	2.75	0.52	0.57	0.49	0.50	0.48
8	हांगकांग	2.70	3.18	2.97	3.09	2.53	1.67	1.10	1.21	1.09	1.51
9	इण्डोनेशिया	2.51	2.52	2.68	2.69	2.50	0.35	0.57	0.46	0.38	0.34
10	ईराक	1.61	1.56	2.48	2.49	2.73	0.07	0.08	0.04	0.03	0.07
11	जापान	2.22	2.21	2.32	2.19	2.29	0.54	0.59	0.52	0.46	0.47
12	बेल्जियम	2.09	2.32	2.22	2.21	1.91	0.62	0.67	0.69	0.71	0.52
13	कवैत	1.93	1.96	2.21	2.02	2.38	0.09	0.18	0.07	0.08	0.06
14	कोरिया	2.57	2.29	2.20	2.20	2.30	0.40	0.36	0.33	0.35	0.29
15	नाईजीरिया	1.86	2.08	2.19	2.19	2.14	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20
	कुल शीर्षस्थ 15 देश	57.84	59.50	60.40	60.16	59.91	0.56	0.55	0.51	0.49	0.50
	कुल व्यापार	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.62**	**0.68**	**0.62**	**0.62**	**0.58**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

टिप्पणी : [क]0 से 1 के बीच आयात एवं निर्यात के सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है तथा एक से अधिक सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक है।

था दो वर्ष के अन्तराल के बाद 4.17 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर पहुंचकर 2011 में संकट पूर्व स्तर को पार कर लिया। वाणिज्यिक सेवाओं की निर्यात वृद्धि दर जो 2000-05 में 11 प्रतिशत के स्तर पर थी वर्ष 2009 में 12 प्रतिशत के स्तर पर ऋणात्मक हो गई और 2011 में पूरी तरह पलट कर 11 प्रतिशत पर जा पहुंची। विश्व व्यापार संगठन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी के अनुसार 2010 में यूरोप के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का पुनरुत्थान हुआ निर्यातों में वृद्धि 4 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 11 प्रतिशत पर पहुंच गई, वहीं उत्तरी अमरीका ने 9 प्रतिशत की समान वृद्धि दर कायम रखी। वर्ष 2010 में क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दक्षिण और केन्द्रीय अमरीका के बाद राष्ट्रमंडल राष्ट्र (सी आई एस) सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र था। एशियाई अर्थव्यवस्था की अपनी वृद्धि दर परिवहन और अन्य वाणिज्यिक सेवाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारण जो 2010 में 23 प्रतिशत थी 2011 में 11 प्रतिशत आधे से भी अधिक थी। वाणिज्यिक सेवाओं की सभी तीन बड़ी श्रेणियों नामश: परिवहन यात्रा और अन्य वाणिज्यिक सेवाओं ने 2011 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। 2012 में सेवा व्यापार में वृद्धि में गिरावट आई जैसाकि डब्ल्यूटीओ की 2012 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है जिसमें निर्यात और आयात वृद्धि को 2012 की दूसरी तिमाही के शून्य और 1 प्रतिशत दर्शाया गया है और पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 2012 की तीसरी तिमाही में -2 प्रतिशत और -1 प्रतिशत दर्शाया गया है। यूरोप की निर्यात और आयात दोनों में -7 प्रतिशत की बहुत अधिक ऋणात्मक वृद्धि थी।

भारत का सेवा व्यापार

भारत का सेवा निर्यात

7.29 भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वर्ष 2001-02 से 2011-12 के दौरान 23.6 प्रतिशत के सीएजीआर पर सेवाओं के निर्यात में बढ़त के साथ पण्य निर्यातों के मुकाबले अधिक तीव्र रही, जबकि पण्य निर्यातों में इसी अवधि में 21.4 प्रतिशत सीएजीआर पर बढ़ोतरी हुई हालांकि सेवा निर्यात में बढ़ोतरी उत्तर वैश्विक संकट अवधि में डांवाडोल हो गई वैश्वि संकट के बाद। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के प्रभाव और विकसित अर्थव्यवस्था में वृद्धि में

आई कमी को प्रतिबिम्बित करते हुए सेवा निर्यातों में 142.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पूर्ववर्ती वर्ष में 29.8 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 14.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि देखी गई। सेवा में निर्यात वृद्धि 2011-12 के पूर्वार्द्ध में 22.7 प्रतिशत के मुकाबले 2012-13 मे पूर्वार्द्ध में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई। (सारणी 7.7)

7.30 लगभग सभी श्रेणियों में सेवा निर्यातों की वृद्धि में गिरावट देखी गई। विविध सेवाएं जो 2012-13 के पूर्वार्ध में कुल सेवा निर्यातों का 75 प्रतिशत के आस-पास बैठती है में पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नरूप अवधि में 20.2 प्रतिशत की तुलना में इस अवधि के दौरान 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। इन विविध सेवाओं के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 46 प्रतिशत है 2011-12 के पूर्वार्ध में 9.8 प्रतिशत पर एक अंक में थी। कुछ श्रेणियों जैसे यात्रा, परिवहन और बीमा सेवाओं में समग्र सेवा निर्यात में हुई कम वृद्धि के चलते ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। वर्ष 2012-13 में नैसकाम ने यूरोप में निरंतर छाए संकट और अमरीकी कारपोरेशन द्वारा मुख्यत: प्रोद्योगिकी पर खर्च कम करने के कारण सूचना प्रोद्योगिकी में अपेक्षाकृत कम निर्यात वृद्धि तथा कारोबारी सेवाओं के 11 प्रतिशत की कमी का पूर्वानुमान लगाया है। जबकि चुनौति का सामना करते हुए वैश्विक आर्थिक वृद्धि जारी है। गार्टनर ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि 2013 में विश्व भर में फैली सूचना प्रोद्योगिकी के खर्च में 4.2 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी (2012 में 3.58 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2013 में 3.73 ट्रिलियन अमरीकी डालर) 2012-13 के पूर्वार्ध में गैर-सॉफ्टवेयर सेवाओं में कारोबारी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 23.9 प्रतिशत के स्तर पर अधिक थी। हालांकि हाल के वर्षों में सेवाओं की इस श्रेणी की निर्यात वृद्धि बेहद अस्थिर रही है। संचार सेवाओं के निर्यात में वृद्धि भी 16.5 प्रतिशत के स्तर पर अधिक थी।

भारत का सेवा आयात

7.31 पूर्ववर्ती वर्ष में सेवा आयातों में 34.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2011-12 में 78.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि 2012-13 के पूर्वार्ध में सेवाओं के आयात में तेजी आई और 2011-12 के पूर्वार्ध 0.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले इसमें 10.3 प्रतिशत की तीव्र बढ़ोतरी हुई। सेवाओं के आयात में यह वृद्धि मुख्यत: सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं के अधिक आयातों के कारण थी जिसमें 2012-13 के पूर्वार्ध में क्रमश: 89.5 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2011-12 के पूर्वार्ध में इन आयातों में क्रमश: 47.5 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। तथापि वित्तीय सेवाओं में 2011-12 के पूर्वार्ध में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 34.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी जो शायद खराब वित्तीय स्थिति का प्रतिबिम्ब है। इसी तरह परिवहन, यात्रा, बीमा के आयातों ने भी 2011-12 के पूर्वार्ध में घनात्मक वृद्धि की तुलना में 2012-13 के पूर्वार्ध में गिरावट दर्ज की गई थी। (सारणी 7.8)

सारणी 7.7 : भारत का सेवा निर्यात

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर	विकास दर*			
	2001-02	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)	2001-02 to 2011-12	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)
यात्रा	18.3	13.0	11.9	10.7	19.4	33.2	16.9	21.3	-5.9
परिवहन	12.6	12.8	13.3	12.1	23.8	27.4	28.0	37.1	-4.8
बीमा	1.7	1.8	1.8	1.6	24.8	22.3	35.3	39.8	-9.3
जीएनआईई	3.0	0.3	0.4	0.4	-0.8	21.3	-10.7	30.6	7.7
विविध	64.4	72.0	72.6	75.2	25.0	29.8	11.3	20.2	8.0
साफ्टवेयर सेवाएं	44.1	43.7	43.3	45.6	23.5	6.8	17.2	21.8	9.8
गैर साफ्टवेयर सेवाएं	20.3	28.3	29.3	29.6	27.8	83.4	3.3	18.1	5.4
जिसका									
व्यवसाय सेवाएं	3.0	18.2	17.8	21.2	47.9	112.4	7.7	10.6	23.9
वित्तीय सेवाएं	1.7	4.2	4.3	3.8	35.2	76.2	-8.3	-6.2	-6.9
संचार सेवाएं	4.4	1.1	1.1	1.3	7.8	27.2	2.4	1.1	16.5
कुल सेवा निर्यात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**23.6**	**29.8**	**14.2**	**22.7**	**4.3**

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं

टिप्पणी: *वृद्धि दर अमरीकी डालर में; जीएनआईई = सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

सारणी 7.8 : भारत का सेवा आयात

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर	विकास दर*			
	2001-02	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)	2001-02 to 2011-12	2010-11	2011-12	2011-12 (अप्रैल-सित.)	2012-13 (अप्रैल-सित.)
यात्रा	21.8	17.6	19.3	15.2	16.4	18.0	24.8	39.4	-12.9
परिवहन	25.1	20.9	21.0	18.9	16.8	16.3	18.0	14.5	-1.0
बीमा	2.0	1.9	2.0	1.4	18.3	8.9	7.0	3.6	-23.3
जीएनआईई	2.0	1.0	1.0	0.8	10.7	56.2	-4.9	9.2	-11.3
विविध	49.0	58.6	56.7	63.7	21.1	44.6	-14.3	-13.4	23.9
साफ्टवेयर सेवाएं	4.9	1.6	1.7	2.9	6.5	49.5	-42.8	-47.5	89.7
गैर साफ्टवेयर सेवाएं जिसका	44.2	56.9	55.0	60.8	22.0	44.4	-13.0	-11.7	21.9
व्यवसाय सेवाएं	10.9	34.2	33.8	37.4	33.4	53.4	-3.3	-4.4	22.0
वित्तीय सेवाएं	9.1	10.2	10.7	6.4	20.2	61.2	6.7	17.7	-34.7
संचार सेवाएं	2.7	2.0	2.0	0.6	15.5	-15.0	35.2	42.8	-66.2
कुल सेवा निर्यात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**18.9**	**34.2**	**-2.9**	**-0.5**	**10.3**

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं

टिप्पणी: *वृद्धि दर अमरीकी डालर के मूल्य पर आधारित है। जीएनआईई = सरकार अन्य कहीं भी शामिल नहीं है।

सेवाओं में भारत का व्यापार संतुलन

7.32 भारत के सेवा निर्यातों के खाते पर अधिशेष हालिया वर्षों में पण्य खाते पर व्यापार घाटे के अधिकांश हिस्से के वित्तपोषण हेतु अनुकूल कारक रही है। वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान सेवा निर्यातों के अधिशेष से पण्य व्यापार घाटे के औसतन लगभग 38 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ। 2011-12 के दौरान 64.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर सेवा निर्यात के खाता पर निवल अधिशेष 2010-11 के मुकाबले पर्याप्त रूप से अधिक है और इसके 33.8 प्रतिशत व्यापार घाटे का वित्तपोषण किया है। 2012-13 के पूर्वार्ध में सेवा निर्यातों में मन्दनकारी वृद्धि और सेवा आयातों में वृद्धि के साथ 2011-12 के पूर्वार्ध में 32.6 प्रतिशत व्यापार घाटे को वित्तपोषित करते हुए अधिशेष 29.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 2.9 प्रतिशत कम था भविष्य की बात करें तो सेवाओं का निर्यात घट जाने का जोखिम बना हुआ है क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्थितियां कम अनुकूल हैं।

व्यापार ऋण

7.33 व्यापार ऋण विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण घटक है। अन्तरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय फर्म व्यापार ऋणों पर पूरी तरह निर्भर होती है 2005-2011 की अवधि हेतु बर्न यूनियन के बीमाकर्ताओं के देश के व्यापार ऋण संबंधी त्रैमासिक आकड़ों का उपभोग करते हुए डब्ल्यू टी ओ के द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के अनुसार एक देश को व्यापार ऋण में दी गई 1 प्रतिशत की गारण्टी उस देश के वास्तविक आयात में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि करती है। इसका प्रभाव संकट और गैर संकट अवधियों में भिन्न नहीं होता इस तरह व्यापार ऋण की उपलब्धता तथा लागत दोनो वित्तीय अनिश्चितताओं के वर्तमान माहौल में महत्वपूर्ण है वही बैंकिंग प्रणाली को सीमापार ऋण जोखिम को घटाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

व्यापार ऋण : भारतीय परिदृश्य

7.34 बेहतर वैश्विक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित करते हुए, सितम्बर, 2012 के अंत तक भारत को दिए जाने वाला अल्पावधिक व्यापार ऋण (1 वर्ष तक) का सकल अन्तर्वाह 392,526 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसने 24.6 प्रतिशत वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाई (लेकिन 2012-13 की दूसरी तिमाही में तिमाही दर तिमाही 1.1 प्रतिशत की गिरावट थी) 2011-12 की तुलना में 2012-13 के पूर्वार्ध में व्यापार ऋण का अन्तर्वाह 57.6 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 14 प्रतिशत अधिक था और व्यापार ऋण के बहिर्वाह में 7.7 प्रतिशत के स्तर पर वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी परिणामस्वरूप निवल व्यापार ऋण 9.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था इसमें 2011-12 के पूर्वार्द्ध में 14.4 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 60.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.35 वर्ष 2011-12 से निर्यात ऋण में गिरावट आ रही है 2012-13 में (30 नवम्बर 2012 तक) यह पूरे वित्त वर्ष 2011-12 में 7.7 प्रतिशत की तुलना में मार्चान्त 2012 के बाद 4.7 प्रतिशत बढ़ गया है। निवल बैंक ऋण के रूप में निर्यात ऋण जो 24 मार्च

सारणी 7.9 : निर्यात ऋण

तिथि को बकाया	निर्यात ऋण (करोड़ रु॰)	अन्तर प्रतिशत	एनबीसी प्रतिशत के के रूप में निर्यात ऋण
24 मार्च 2000	39118	9.0	9.8
23 मार्च 2001	43321	10.7	9.3
22 मार्च 2002	42978	-0.8	8.0
21 मार्च 2003	49202	14.5	7.4
19 मार्च 2004	57687	17.2	7.6
18 मार्च. 2005	69059	19.7	6.3
31 मार्च 2006	86207	24.8	5.7
30 मार्च 2007	104926	21.7	5.4
28 मार्च 2008	129983	23.9	5.5
27 मार्च 2009	128940	-0.8	4.6
26 मार्च 2010	138143	7.1	4.3
25 मार्च 2011	168841	22.2	4.3
23 मार्च 2012	181852	7.7	3.9
30 नवम्बर 2012	185803	4.7*	3.7

स्रोत : आरबीआई

टिप्पणी *: 18 नवम्बर 2011 के बाद अन्तर

एनबीसी: निवल बैंक ऋण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़ों में, आरबीआई से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरवी) के आंकड़ों को अलग रखा गया है।

2000 की स्थिति के अनुसार 9.8 प्रतिशत के स्तर पर था कई वर्षों से लगातार घट रहा है 30 नवम्बर 2012 की स्थिति अनुसार 2012 में यह 3.7 प्रतिशत ओर कम हो गया (सारणी 7.14) वैश्विक मंदी और निर्यात की बिगड़ती वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने निर्यातकों को बैंक ऋण की उपलब्धता सुलभ करने के लिए कई उपाय किए हैं (बाक्स 7.4 देखें)

व्यापार नीति

हालिया व्यापार नीति संबंधी उपाय

7.36 सरकार ने 5 जून 2012 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के वार्षिक अनुपूरक विवरण में व्यापार नीति संबंधी कई उपायों की घोषणा की है निर्यात में सहायता हेतु इस वर्ष के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2012-13 में और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक और ऋण संबंधी नीतियों में भी कई उपाय किए गए थे जो इस प्रकार हैं। (बॉक्स 7.4)

राज्य-वार निर्यात संवर्धन के लिए नीति

7.37 2011-12 में भारत के निर्यात में पांच शीर्षस्थ राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थे जिनका कुल निर्यात भारत के निर्यात का 63.4 प्रतिशत था। यद्यपि 2011-12 में इन पांच राज्यों का उच्च मजबूत विकास (गुजरात के अलावा, जिसका 5.5 प्रतिशत विकास था) था, वहीं 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में इन सभी का ऋणात्मक विकास था। वस्तुत: 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में उड़ीसा के अलावा सभी अन्य शीर्ष 15 राज्यों का सकारात्मक विकास था जिसमें से 2011-12 में मजबूत विकास के साथ-साथ 2012-13 में केरल, राजस्थान और पंजाब का उच्च निर्यात विकास हुआ। हरियाणा का निर्यात विकास भी 2012-13 (अप्रैल-नवम्बर) में अपेक्षाकृत उच्च था हालांकि 2011-12 में यह कम था। सारणी 7.15 में दिया गया राज्य-वार निर्यात केवल निर्देशात्मक है क्योंकि आंकड़ों में कतिपय कमियां हैं, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में वर्णित है।

7.38 राज्यों के निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध क्रियाकलापों के विकास के लिए सहायता योजना (एएसआईडीई), निर्यात के विकास एवं वृद्धि के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को सहायता प्रदान करती है। एएसआईडीई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2012-13 आर.ई. के लिए बजट परिव्यय 655.5 करोड़ रू. है जिसमें से 573.07.07 करोड़ रू. जनवरी 2013 के अंत तक स्वीकृत/जारी किया जा चुका है। परिव्यय के दो घटक हैं: राज्य (कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत) और केन्द्रीय (कुल परिव्यय का 20 प्रतिशत)। एएसआईडीई के राज्य घटक के तहत राज्य-वार आबंटन यह दर्शाता है कि 2012-13 में आवंटन की दृष्टि से शीर्षस्थ पांच राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनार्टक और आंध्र प्रदेश हैं जो निर्यात में भी पांच शीर्षस्थ राज्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में, महत्वपूर्ण आवंटन वाले राज्य असम, मेघालय और त्रिपुरा हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

7.39 चूंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम और नियमावली फरवरी, 2006 में अधिसूचित किया गया था, 585 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से 385 को अधिसूचित किया गया। एसईज़ेड लागू होने के बाद संपूर्ण तौर पर कुल 9,45,990 लोगों को एसईजेड में प्रदान किए गए रोजगार में से 8,11,286 लोगों को फरवरी 2006 के बाद सृजित वृद्धिशील रोजगार मिला। यह अवसंरचना क्रियाकलापों के लिए विकासकर्ता द्वारा सृजित रोजगार के लाखों श्रम दिनों के अलावा है। यद्यपि 2010-11 में एसईजेड से वास्तविक निर्यात का मूल्य 3,15,867.85 करोड़ रु. था, 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2011-12 में यह आंकड़ा 3,64,477,73 करोड़ रु. तक पहुंच गया। वर्तमान वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में एसईजेड से कुल वास्तविक निर्यात पूर्व वर्ष की संगत अवधि में निर्यात पर 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 239628.78 करोड़ रु. तक हो गई। 30 सितम्बर, 2012 तक एसईजेड में कुल निवेश नए अधिसूचित क्षेत्रों में 2,14,759.90 करोड़ रु. सहित लगभग 2,18,795.41 करोड़ रु. था। एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एसईजेड में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। कुल 160

बॉक्स 7.4 : व्यापार नीति संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण उपाय

बजट से संबंधित

- तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2015 तक मूलत: 5 प्रतिशत को सीमाशुल्क की पूरी छूट देते हुए उर्वरक परियोजना के विस्तार अथवा आरंभिक शुरूआत के लिए उपस्करों का आयात; यूरिया को छोड़कर कुछ जल-विलेय उर्वरको और तरल उर्वरकों, में सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- मण्डियो में पैलेट रैंकिंग सिस्टम और अर्मेन्डाइज हेंडलिंग सिस्टम के स्थापन हेतु रियायती आयात शुल्क अथवा बागवानी उत्पाद के लिए गोदामों का विस्तार किया गया।
- कोयला-खनन परियोजना के लिए बुनियादी सीमा शुल्क में पूरी छूट।
- लोह अयस्क पैलेट संयत्र अथवा लौह अयस्क वेनेफिकेशन संयत्र के सम्पूर्ण विस्तार अथवा स्थापना के लिए आयतित मशीनरी तथा संयेत्रों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- ओटोमेटिक शटल-लेस लूम्स पर लगाए गए 5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क में पूरी छूट।
- मानक स्वर्ण छड़ो; 99.5 प्रतिशत से भी अधिक की शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्को और प्लेटिनियम पर बुनियादी सीमा शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया और गैर मानक स्वर्ण पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया

ऋण से संबंधित

- नवम्बर 2011 में आरबीआई ने विदेशी वाणिज्यिक उधारों की आल इन कास्ट रोलिंग 3 से 5 वर्ष की परिपक्व अवधि के लिए 6 माह के लिबोर/यूरोलिवोर/यूरिवोट के बाद 350 आधार बिन्दु और पांच वर्ष से अधिक की परिपक्व अवधि के लिए 6 माह के लिवोर/यूरो लिवोर/यूरिवोर के बाद 500 आधार बिन्दु तक बढ़ाई। तदनुसार व्यापार ऋण संबंधी आल इन कास्ट सेलिंग 31 मार्च 2013 तक 6 माह के लिबोर/यूरो लिबोर/यूरिबोर के बाद 350 आधार बिन्दु तक भी बढ़ाई।
- 5 मई 2012 से बैंकों को निर्यातकों के लिए निधियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण संबंधी अपनी ब्याज दरे निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी।
- 18 जून 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2012 से अनुसूचित बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा की पात्रता सीमा, जो बकाया निर्यात ऋण के पुनर्वित के लिए 15 प्रतिशत थी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी थी। इसका उद्देश्य बैंकों को 300 बिलियन रू. से अधिक की राशि पर अतिरिक्त नकदी सहायता प्रदान करना था। नकद समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अन्तर्गत इसीआर सुविधा से संबंधित लगाई गई ब्याज दरे चालू रेपा दर पर कायम रही।
- 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना जो पहले हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एसएमइ के लिए उपलब्ध थी को विस्तार करके श्रम प्रधान क्षेत्रों अर्थात खिलौने, खेल संबंधी वस्तुओं प्रसस्कृत कृषि उत्पादों और तैयार कपड़ों के लिए भी 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च 2013 तक कर दिया गया। इसे आगे 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया और इंजीनियरिंग वस्तुओं की 134 टेरिफ लाइने भी इस योजना में शामिल की गई।

2012-13 के विदेश व्यापार नीति संबंधी उपाय

- वर्धित निर्यात संबंधी प्रोत्साहन: जनवरी-मार्च 2012 की आधार अवधि के बाद जनवरी-मार्च 2013 की अवधि के दौरान किए गए वर्धित निर्यात पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन आयातक और निर्यातक कोड (आईईसी) धारक को इस विशेष अवधि अर्थात जनवरी-मार्च 2013 के दौरान अमरीका ईयू और एशियायी देशों को किए गए निर्यातों की 2 प्रतिशत वर्धित दर पर दिए जाएंगे।
- निर्यात सवर्धन पूंजीगत वस्तु (इपीसीजी) योजना: शून्य शुल्क इपीसीजी योजना 31 मार्च 2013 तक बढ़ाई गई और इसका क्षेत्र विस्तृत किया गया। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात बाध्यता उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्पादों के निर्यात के लिए सामान्य निर्यात बाह्यता 25 प्रतिशत होगी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अभिज्ञात भूमि कस्टम स्टेशनों के जरिए विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यातों की फ्री ऑन बोर्ड पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है।

  हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद की निर्यात संबंधी सहायता: 16 अभिज्ञात हरित प्रोद्योगिकी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इपीसीजी योजना के अन्तर्गत इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए निर्यात बाह्यता सामान्य निर्यात बाह्यता से 75 प्रतिशत घटा दी गई है।
- कृषि क्षेत्र हेतु अवसंरचना के लिए सहायता: आईटीसी (एचएस) अध्याय 1 से अध्याय 24 (दोनों सम्मिलित) के अन्तर्गत उत्पादों का निर्यात करने वाले हैसियत धारकों ने शीतागार इकाइयां, पैक-हाउस आदि के लिए पूंजीगत वस्तुओं एवं उपकरणों के आयात के अलावा पैक-हाउस की स्थापना के लिए 14 विनिर्दिष्ट उपकरणों के आयात के लिए ऐसे निर्यातित कृषि उत्पादों के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट शेयर प्रदान किया।
- गहन-श्रम क्षेत्रों में निवेश संवर्धन के लिए प्रोत्साहन: हैसियत धारकों ने कतिपय विनिर्दिष्ट गहन-श्रम क्षेत्रों यथा-चमड़ा, कपड़ा एवं जूट, हस्तशिल्प, लास्टिक एवं मूल रसायनों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेश संवर्धन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए हैसियत धारक प्रोत्साहन शेयर (एसएचआईएस) जारी किया है। इन शेयरों के मूल्य का 10 प्रतिशत तक पहले आयातित पूंजीगत वस्तुओं के अवयवों और पुर्जों के आयात हेतु उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(जारी....)

बॉक्स 7.4 : व्यापार नीति संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण उपाय (जारी...)

- बाजार एवं उत्पाद विविधता: सात नए बाजारों का फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) तथा सात को विशेष फोकस मार्केट स्कीम (विशेष एफएमएस) में जोड़ा गया है। छियालीस नई मदों को बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में जोड़ा गया है। एमएलएफपीएस को अध्याय 61 और अध्याय 62 के अन्तर्गत आने वाले मदों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 31 मार्च, 2013 तक विस्तारित किया गया है। फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) में लगभग 100 नए मदों को जोड़ा गया है। तीन नए मदों को विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में जोड़ा गया है।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण: इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अग्रिम अधिकार (एए) किस इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) पोर्ट में पंजीकृत है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) पोर्ट में अग्रिम अधिकार (एए) के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गई है। दिल्ली और मुंबई से डाक, कुरियर या ई-कॉमर्स के माध्यम से भेजा गया निर्यात लदान एफटीपी के अन्तर्गत निर्यात लाभ के लिए पात्र होगा।
- नई 'ई-बीआरसी' पहल: एक मुख्य ईडीआई पहल 'ई-बीआरसी' शुरू किया गया है जो दैनिक आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सर्वर को संबंधित बैंक से विदेश विनिमय प्राप्ति के इलेक्ट्रॉनिक संचार की सूचना देगा। इससे बैंक निर्यात और उगाही प्रमाणन (बी.आर.सी.) जारी करने के लिए निर्यातक को बैंक से कार्य अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी।

एसईजेड वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कर रही हैं। इनमें से 93 आईटी/आईटीईएस, 17 बहु-उत्पाद और 50 अन्य क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड हैं। इन एसईजेड में कुल इकाइयों की संख्या 3308 है।

आकस्मिक व्यापार नीति एवं गैर-प्रशुल्क उपाय

7.40 सभी देशों द्वारा 2001 में उच्च स्तर पर शुरू की गई एंटी-डम्पिंग जांच 2007 तक लगभग कम हो गया। 2008 में वे एक बार फिर उठ खड़े हुए किन्तु 2011 तक घटकर निम्न स्तर पर पहुंच गए। तथापि, 2011 (जून तक) में 68 के मुकाबले 2012 में 114 जांचों (जून तक) के साथ वे फिर से बढ़ गए। 2011 में भारत ऐसी जांच शुरू करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा, किन्तु 2012 में (जून तक) ब्राजील शीर्ष पर है जिसके बाद अर्जेंटीना और कनाडा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रत्येक के सात जांच कर्ताओं के साथ चौथे स्थान पर हैं (सारणी 7.10)।

7.41 2012-13 (1.42012 से 31.12.2012) के दौरान एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा 10 नए मामले शुरू किए गए। इन जांचों में शामिल देश चीन लोक गणतंत्र, यूरोपीय संघ, कोरिया लोक गणतंत्र, मलेशिया, मेक्सिको, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

तालिका 7.10 : डंपिंगरोगी उपाय 1995-2012 शीर्ष 10 उपयोगकर्त्ताओं द्वारा शुरू की गई जांच

देश	1995	2001	2002	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2011 जन.-जून	2012 जन.-जून	1995-2012*
भारत	6	79	81	46	28	47	55	31	41	19	10	7	663
स. रा. अमरीका	14	77	35	37	12	28	16	20	3	15	9	7	465
यूरोपीय संघ	33	28	20	7	24	9	19	15	15	17	8	7	444
अर्जेण्टीना	27	28	14	1	12	8	19	28	14	7	4	10	301
ब्राजील	5	17	8	4	6	13	23	9	37	16	11	26	258
आस्ट्रेलिया	5	24	16	8	7	2	6	9	7	18	2	6	241
द॰ अफ्रीका	16	6	4	8	23	5	3	3	0	4	1	0	216
चीन	0	14	30	22	24	4	14	17	8	5	0	4	195
कनाडा	11	25	5	15	1	1	3	6	2	2	0	10	165
तुर्की	0	15	18	11	12	6	23	6	2	2	1	6	154
सभी देश	157	372	315	234	201	165	213	209	172	155	68	114	4125

स्रोत : डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ *जून 2012 तक

7.42 यद्यपि ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन)-डब्ल्यूटीओ-यूएनसीटीएडी (संयुक्त राष्ट्री व्यापार एवं विकास सम्मेलन) की जी-20 (20 का समूह) पर अक्तूबर 2012 की संयुक्त रिपोर्ट में व्यापार एवं निवेश उपायों में प्रतिबधात्मक व्यापार उपायों में कमी की ओर इशारा किया गया किन्तु वैश्विक संकट की निरन्तरता ने सरकारों पर आकस्मिक व्यापार नीतियों एवं गैर-प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) का सहारा लेने के लिए राजनैतिक और आर्थिक दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त पिछले पांच माह में कार्यान्वित नए उपायों को वैश्विक संकट फैलने के बाद अपनाए गए प्रतिबंधों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित या संभावित रूप से प्रतिबंधित करने वाला माना जा सकता है। समाप्त किए गए प्रतिबंधात्मक उपायों के अलावा अक्टूबर 2008 से जारी रखे गए प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार क्षेत्र विश्व उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत और जी-20 अर्थव्यवस्था के व्यापार का 4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

डब्ल्यूटीओ वार्ताएं और भारत

7.43 डब्ल्यूटीओ में दोहा दौर की व्यापार वार्ता, जो 2001 में शुरू हुई वह विभिन्न मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण अधूरी रही। जेनेवा में दिसम्बर 2011 में डब्ल्यूटीओ की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्यों को शामिल मुद्दों के समाधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए। तथापि, 2012 में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। दिसम्बर 2013 में आयोजित होने वाली डब्ल्यूटीओ की नौवीं मंत्रिस्तरीय कांफ्रेंस (एमसी 9) के लिए समय पर कुछ मुद्दों पर जल्दी परिणाम निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का यह मत है कि वार्ता का शीघ्र परिणाम विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं (एसवीई) के हितों के मुद्दों को निरपवाद रूप से सुलझाएगा।

7.44 डब्ल्यूटीओ सदस्यों 14 दिसम्बर, 2009 को व्यापार सुविधा पर एक समेकित वार्ता पाठ मसौदा बनाया गया। व्यापार सुविधा पर वार्ता समूह (एनजीटीएफ) की बैठकों में चर्चाओं के माध्यम से मसौदा पाठ को अब तक चौदह बार (दिसम्बर, 2012 तक) संशोधित किया गया है। भारत इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और इसने 'सीमाशुल्क सहयोग', 'सीमाशुल्क संघ की त्वरित अलर्ट प्रणाली' और 'अपील तंत्र' पर कुछ प्रस्ताव भी पेश किया है। तथापि, मसौदा पाठ में आंतरिक संतुलन की कमी है। विकसित देश अपने ही देशों के कानूनों और प्रक्रिया को निर्देशचिह्नों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और विकासशील देशों से उनको दोहराने की इच्छा रखते हैं। विकासशील देशों ने वार्ता में कुल मिलाकर एक रक्षात्मक रुख अपनाया हुआ है। एलडीसी सामान्यतया कोई बाध्यकारी वचन नहीं देना चाहते हैं। क्षमता बाध्यता और संसाधनों की कमी दो मुख्य घटक हैं जो विकासशील (एलडीसी सहित) को व्यापार सुविधा में बाध्यकारी वचन देने से रोक रहे हैं। वर्तमान संकेत यह हैं कि विकसित देश और अन्य दाता इन देशों में भौतिक अवसरंचना के निर्माण में निवेश नहीं करेंगे, हालांकि वार्ता अधिदेश वचनबद्धता को स्पष्ट रूप से अवसंरचना विकास के लिए समर्थन और सहायता से संबद्ध करता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस संबद्धता का सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों, विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा सम्मान किया जाए और बचनबद्धता के कार्यन्वयन के लिए समुचित सहायता प्रदान किया जाए।अधिकतर विकासशील देशों के साथ भारत यह चाहता है कि बाजार पहुंच और व्यापार सुविधा, शुल्क मुक्त कोटा, एलडीसी के लिए अबाध बाजार पहुंच और कपास पर इमदाद कम करने के लिए तौर-तरीकों की स्वीकार्यता जैसे विकासात्मक मुद्दों के साथ संतुलित हों। जी33 देशों का समूह, जो भारत सहित 46 विकासशील देशों का एक गुट है, ने 16 नवम्बर, 2012 को डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा पर एक प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों को अपने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग प्रचालनों में और अधिक लचीलेपन की अनुमति देने हेतु कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करने के लिए है। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और व्यापार सुविधा मोर्चे पर कोई रियायत एमसी9 के लिए किसी पैकेज सौदे में जी33 प्रस्ताव की स्वीकार्यता द्वारा संतुलित किए जाने की आवश्यकता है।

7.45 वर्तमान वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटी-1) के कुछ विकसित सदस्य देशों, अर्थात्, यूएसए, यूरोपीय संघ एवं जापान ने आईटी उत्पादों, जिन पर सीमा शुल्क शून्य होगा, के क्षेत्र को बढ़ाने; गैर-प्रशुल्क उपायों के समाधान; और अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे नए हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या बढ़ाने हेतु आईटीए-2 का प्रस्ताव रखा। आईटीए विस्तार के समर्थनों ने लगभग 350 आईटी उत्पादों (आईटी-2) का प्रस्ताव रखा। आईटीए विस्तार के समर्थकों ने लगभग 350 आईटी उत्पादों (आईटी-2 के सभी समर्थकों के हितों के उत्पादों को शामिल करते हुए एक समेकित सूची तैयार की है जिन पर प्रशुल्क की कमी की मांग की जा रही है। यह डब्ल्यूटीओ में सक्रिय रूप से विचाराधीन है और भारत इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर रहा है।

7.46 सेवाओं में वार्ताएं मुख्यतया बहुपक्षीय प्रारूप में जारी रहीं। 2009, 2010 और 2011 के पूर्वार्ध तक गहन वार्ताएं आयोजित की गईं। ये प्रयास सेवाओं में व्यापार पर समिति-विशेष सत्र (सीटीएस-एसएस) के अध्यक्ष और अप्रैल 2011 में सीटीएस के तहत सभी अधीनस्थ निकायों द्वारा एक रिपोर्ट में समाप्त हुए। अध्यक्ष की रिपोर्ट से दो मत उत्पन्न हुए। विकसित देशों की राय यह है कि बाजार पहुंच में और प्रगति में, जहां भी संभव हो वहां पर स्वतंत्र उदारीकरण का बंधन, वाणिज्यिक मौजूदगी के तहत पहुंच के बेहतर स्तर, अर्थात्, मोड 3 (विदेशी इक्विटी और वाणिज्यिक मौजूदगी के प्रकार पर प्रतिबंध सहित), के साथ-साथ मोड 4 में सुदृढ़ व संतोषजनक परिणाम (स्वाभाविक व्यक्ति की

बॉक्स 7.5 : भारत की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था: अद्यतन गतिविधियां

- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (साफ्टा):** सॉफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को हस्ताक्षर किया गया और यह 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। साफ्टा के तहत, भारत ने अल्कोहॉल और तम्बाकू से संबंधित 25 मदों के अलावा सभी मदों पर सभी एलडीसी, यथा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को शून्य बुनियादी सीमाशुल्क प्रदान किया है। साफ्टा समझौते के तहत, भारत ने गैर-एलडीसी के लिए साफ्टा संवेदशील सूची को 6 सितम्बर, 2012 से 264 प्रशुल्क सीमा को कम करके 878 से 614 किया है।

- **भारत थाईलैंड एफटीए, भारत-थाईलैंड एफटीए की स्थापना हेतु समझौते की रूपरेखा के अंतर्गत शीघ्र उपज योजना (ईएचएस):** 9 अक्तूबर, 2003 को भारत और थाईलैंड ने भारत-थाईलैंड एफटीए की स्थापना हेतु समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए जिसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र को एकल उपक्रम के रूप में निश्चित करना शामिल था। ईएचएस के अन्तर्गत, 1 सितम्बर, 2004 और 31 अगस्त 2006 के बीच दोनों पक्षों द्वारा साथ-साथ 82 समान मदों की सूची पर प्रशुल्क धीरे-धीरे समाप्त किया गया। भारत-थाईलैंड एफटीए के तहत, आसियान से अधिक प्रशुल्क रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है। अब तक भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति (आईटीटीएनसी) की बैठकों के 26 दौर आयोजित किए गए हैं। अंतिम दौर 26-27 नवम्बर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- **भारत आसियान समय आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए):** सेवा एवं निवेश समझौता। वस्तुओं में व्यापार समझौता जिस पर भारत और आसियान ने बीच सीईसीए की वृहद रूपरेखा के अन्तर्गत 13 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किया गया और यह पहले ही लागू हो चुका है। 20 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मरणीय सम्मेलन के दौरान सेवा समझौते और निवेश समझौते के लिए वार्ता के निष्कर्ष की घोषणा की गई। इन समझौतों के लिए कानूनी परिश्रमी फरवरी 2013 तक पूरा किया जाएगा। समझौते पर अगस्त 2013 में आसियान आर्थिक मंत्रियों (एईएम) भारत परामर्श के दौरान हस्ताक्षर किया जाएगा।

- **आसियान + 6 (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड) के बीच क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौता:** अप्रैल 2012 में कम्बोडिया में आसियान के 20वें सम्मेलन के दौरान, आसियान देश, आसियान और इसके एफटीए साझेदारों को शामिल करते हुए एक आरसीईपी की स्थापना के लिए सहमत हुए। आरसीईपी वार्ता शुरू करने का उद्देश्य आसियान सदस्यों एवं आसियान के एफटीए साझेदारों के बीच एक आधुनिक, सामग्र उच्च गुणवत्ता और परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी करार बनाना था। आरसीईपी में वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, बौद्धिक सम्पत्ति, प्रतिस्पर्धा, विवाद समाधान और अन्य मुद्दों का समावेश होगा।

- **भारत-यूरोपीय संघ वृहद् आधारित व्यापार एवं निवेश समझौता(बीटीआईए):** अब तक वार्ता के पन्द्रह दौर और कई अंतर-सत्रात्मक एवं मुख्य मध्यस्थ स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया है। 15वां दौर 4-7 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी):** विकासशील देशों के बीच जीएसटीपी की स्थापना करने वाले इस समझौते पर वार्ता के पहले दौर के समापन के बाद 13 अप्रैल 1988 को बेलग्रेड में हस्ताक्षर किए गए। तैतालीस देशों ने समझौते को मंजूर किया और सहभागिता की। भारत ने आयात की तारीख को प्रचलित लागू प्रशुल्कों पर 20 प्रतिशत के सीमापारीय अधिमान अंतर (एमओपी) के साथ शुल्कदेय प्रशुल्क सीमाओं के 70.08 प्रतिशत पर प्रशुल्क रियायत की पेशकश की है। भारत ने अपने सभी शुल्कदेय प्रशुल्क सीमाओं के 77 प्रतिशत पर 25 प्रतिशत का एमओपी प्रदान कार्य की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 23 अगस्त, 2012 की अपनी बैठक में भारत के रियायत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दे दी हैं। प्रशुल्क रियायत को न्यूनतम चार सहभागियों द्वारा अपने रियायत कार्यक्रम को मंजूरी देने के तीस दिनों के बाद कार्यान्वित किया जाना है। अब तक भारत और मलेशिया ने अपने कार्यक्रमों को मंजूरी दी है।

स्रोत : वणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

मौजूदगी) को शामिल किया जा सकता है। विकासशील देशों की राय यह है कि बाजार पहुंच वार्ता में एक असंतुलन है, जैसा कि इस तथ्य से जाहिर है कि विकासशील देशों के लचीलेपन को अन्य सदस्यों के अनुरोधों में ध्यान में नहीं रखा गया, विकासशील देशों के निर्यात हित के क्षेत्रों को विकसित सदस्यों की पेशकशों में पूर्णतया नहीं दर्शाया जा रहा है; विकाशील देशों ने पहले ही दोहा दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; और कुछ पार्श्वगौण अनुरोध और हाल के प्रस्तावों ने महत्वकांक्षा का एक स्तर प्रस्तुत किया है जो हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र के अनुबंध ग में सहमति से परे है। भारत ने पहले ही अपने संशोधित पेशकश में काफी सुधार किया है (उरूग्वे दौर में 37 उप-क्षेत्रों से संशोधित पेशकश में 95) कुछ प्रमुख विकसित सदस्य देशों ने अपने मोड 4 पेशकश में शून्य या बहुत कम गतिविधि दर्शाया है, जो हमारे लिए रुचि का क्षेत्र है।

द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग

7.47 भारत हमेशा से एक खुले, निष्पक्ष, पूर्वानुमेय, गैर-विभेदकारी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (एमटीएस) के पक्ष में रहा है, यह हाल के वर्षों में व्यापार में उदारीकरण प्राप्त करने और एमटीएस के पूरकीकरण हेतु मूलभूत अंग के रूप में कार्य करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) में भी सक्रिय रहा है। अब तक, भारत ने 10 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटी) और 5 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और ये एफटीए/पीटीए पहले से ही लागू हैं। इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में 17 एफटीए पर वार्ता कर रहा है जिसमें कुछ विद्यमान समझौतों की समीक्षा/विस्तार शामिल हैं। (बॉक्स 7.5 देंखे)

बाक्स 7.6 : क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी सधन निर्यातों का विविधिकरण

वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिवेश में अन्तर्राष्टीय व्यापार में दो प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं। पहला, प्रौद्योगिकी-वृद्धिकर-निर्यातों का बढ़ता हुआ महत्व और दूसरा, क्षेत्रीय व्यापार की बढ़ती हुई भूमिका।

प्रौद्योगिकी प्रधानता के आधार पर व्यापार योग्य उत्पादों को पांच विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। (1) प्राथमिक उत्पादों में तुलनात्मक श्रेष्ठता धारण करने के लिए बहुत कम प्रौद्योगिकी आधार है, (2) सामान्यता प्राकृतिक संसाधनों की स्थानीय उपलब्धि और सरल एवं श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाले तुलनात्मक श्रेष्ठता वाले संसाधन आधारित उत्पाद, (3) निम्न प्रवेश अवरोध के साथ निम्न-स्तर अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रचालन करने वाली और प्रतियोगात्मकता में श्रम, लागत का प्रमुख अवयव का गठन करके पूंजीगत उपकरण में मुख्य रूप से सम्मिलित सरल प्रौद्योगिकी वाले निम्न प्रौद्योगिकी उत्पाद, (4) मध्यम प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद जिनमें जटिल प्रौद्योगिकीयों के साथ उत्पाद विकास के स्थान पर पूंजीगत और मध्यवर्ती उत्पादों में दक्षता और श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का समावेश है और उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय शामिल है जिसमें काफी लंबी अभ्यास अवधि है और जो उच्च प्रवेश अवरोध के अधीन है, (5) उच्च आरएंडडी निवेश, परिष्कृत अवसंरचना, विशेषीकृत तकनीकी दक्षता का उच्च स्तर और फर्मों एवं विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के बीच नजदीकी संपर्क की अपेक्षा वाले उत्पाद डिजाइनों पर बल के साथ उन्नत और तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी वाले उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद। वैश्विक व्यापार में प्रवृत्तियां यह दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकी प्रधान निर्माण उत्पादों में व्यापार का प्रसार हो रहा है। व्यापार के विश्वव्यापी रूप से सक्रिय उत्पादों में, उच्च और मध्यम प्रौद्योगिकी प्रधान मदों का महत्वपूर्ण अनुपात है। भारत, 2004-2011 के दौरान भारत के कुल निर्यात से अधिक गति से बढ़ रहे उच्च प्रौद्योगिकी एवं मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पादों के साथ काफी सफलता से प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों में विविधता ला रहा है। (सारणी 1)। इसके अतिरिक्त, और अधिक प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पाद समूह को शामिल करने के लिए भारत के निर्यात में विविधता लाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सारणी 1. प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों के साथ भारत का व्यापार

		सीएजीआर		
		2004 से 2007	2007 से 2011	2004 से 2011
1	प्राथमिक उत्पाद	25.3	17.6	20.8
2	संसाधन आधारित उत्पाद	32.4	20.0	25.2
3	निम्न प्रौद्योगिकी उत्पाद	13.3	14.5	14.0
4	मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पाद	27.0	20.0	23.0
5	उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद	26.6	26.9	26.8
	कुल निर्यात	24.3	18.8	21.2

वर्तमान वैश्विक व्यापार परिवेश में, निर्यात संवर्धन को क्षेत्रीय पद्धति के माध्यम से और अधिक युक्तिपूर्वक जारी रखा जाता है। भारत का संयुक्त वार्षिक विकास दर (सीएजीआर), 1999-2000 से 2010-11 के दौरान 19.1 प्रतिशत के संपूर्ण निर्यात सीएजीआर के मुकाबले 100 से अधिक देशों (उनके साथ भारत के निर्यात स्तर, उनमें से कुछ में भारत की सदस्यता और अफ्रीका सहित अन्य महाद्वीपों के साथ भारत के व्यवसाय पर आधारित) को शामिल करते हुए यहां पर विचार किए गए अधिकतर 21 आरटीए से तेज है (सारणी 2)। क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से भारत के निर्यात के लिए एशिया एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों में निर्यात संभावना विभिन्न आरटीए में भिन्नव होता है। विभिन्न क्षेत्रीय गुटों में निर्यात संभावना उत्पादों का उनकी प्रौद्योगिकी प्रबलता में वियोजन उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद खंडों में भारत के लिए व्यापार विविधिकरण की संभावना को दर्शाता है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि भारत अपने प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों के निर्यात को आरटीए तक ले जा सकता है। ईयू, नाफ्टा, आरसीईपी, आप्टा, आसियान, आईओआर-एआरसी आदि प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों के लिए बड़े व्यापार अवसरों के साथ महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य हो सकते हैं, यद्यपि इनमें से कुछ क्षेत्रीय व्यवस्थाएं अतिव्यापन करती हैं।

(जारी....)

बाक्स 7.6 : क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी सघन निर्यातों का विविधिकरण (जारी...)

सारणी 2: चुनिंदा आरटीए/एफटीए के साथ भारत की निर्यात उपलब्धि

आरटीए	संस्थापन वर्ष	निर्यात का मूल्य (मिलियन (अमरीकी डालर) 2010-11	निर्यात में हिस्सेदारी % 1999-2000	निर्यात में हिस्सेदारी % 2010-11	निर्यात सीएजी 2010-11, 1999-2000	व्यापार रोपोर्ट इकाईयां (बिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रत्येक आरटीए में उपलब्ध कुल अवसरों में हिस्सेदारी (%) प्राथमिक उत्पाद	संसाधन आधारित	निम्न प्रौद्योगिकी	मध्यम प्रौद्योगिकी	उच्च प्रौद्योगिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत की सदस्यता के साथ											
आईओआर-एआरसी	1997	77097	17.9	30.7	25.1	51.8	22.5	17.5	11.3	28.0	20.6
आरसीईपी/ईएएस	2005	51723	14.7	20.6	22.8	155.3	27.3	18.9	8.5	23.3	22.0
बीआईएमएसटी-ईसी	1997	11673	4.8	4.7	18.6	9.1	38.0	10.8	11.9	24.9	14.4
एसआरआरसी	1985	11634	3.9	4.6	21.0	2.5	33.1	25.4	9.7	23.1	8.7
आईबीएसए	2003	7948	1.1	3.2	30.6	11.2	19.8	17.2	7.9	38.8	16.3
व्यापार करार के साथ प्रस्तावित											
ईयू	1992	45980	26.2	18.3	15.3	205.2	19.9	17.8	16.6	30.4	15.3
जीसीसी	1981	42395	8.7	16.9	26.5	10.0	14.8	17.0	17.1	40.6	10.4
एएसईएएन	1967	25600	6.1	10.2	24.8	35.1	24.7	17.9	9.8	24.5	23.1
सीओएमईएसए	1994	7128	2.3	2.8	21.6	3.8	21.1	29.7	10.5	30.5	8.2
एमईआरसीओएसयूआर	1991	4730	0.7	1.9	30.4	12.2	14.1	18.6	9.2	41.9	16.2
एसएसीयू	1969	4118	0.8	1.6	27.2	3.7	22.9	17.8	9.9	34.5	14.9
व्यापार करार के बिना											
एनएएफटीए	1992	27538	24.8	11.0	10.6	93.8	17.8	13.1	14.9	33.6	20.6
एपीटीए	1975	25887	5.9	10.3	25.4	79.5	25.0	19.6	6.2	24.9	24.3
एसएडीसी	1992	8158	1.9	3.3	25.3	5.3	19.1	24.1	10.2	34.0	12.6
एलएआईए	1980	7443	1.5	3.0	26.4	28.4	12.1	17.4	12.9	39.2	18.4
ईएसी	1967	3994	0.7	1.6	29.0	0.9	12.9	47.1	7.3	25.3	7.3
ईसीओडब्ल्यूएएस	1975	3842	1.5	1.5	19.6	3.3	29.8	31.6	12.3	20.6	5.6
सीआईएस	1991	2607	2.9	1.0	8.5	14.8	12.3	15.1	14.2	42.0	16.4
ईसीसीएएस	1985	1122	0.1	0.4	33.6	0.3	13.7	30.0	14.9	33.0	8.3
द्विपक्षीय व्यापार करार के साथ											
आईएसएलएफटीए	2000	3503	1.8	3.9	27.7	0.6	20.2	19.1	6.3	20.5	34.0
आईएससीईसीए	2003	9816	1.4	1.4	19.4	0.1	25.8	30.7	16.1	22.5	4.9

* संस्थापन लागू करने का वर्ष

केंद्रित उत्पाद-बाजार विविधिकरण व्यापार और विपण्न रणनीतियां भारत के व्यापार बास्केट के विविधिकरण के लिए आवश्यक रूप से अपरिहार्य होगा, विशेष रूप से लक्षित आरटीए में उच्च और मधयम प्रौद्योगिकी प्रधान उत्पादों के पक्ष में, हालांकि इस प्रकार का फोकस कुछ आरटीए द्वारा हमारी कृषि और ग्रामीण समुदायों के महत्वपूर्ण भाग के जीवनयापन के महत्व के प्राथमिक उत्पादों पर ध्यान केंद्रीत करने के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने में सहायक हो सकता है, आरटीए वार्ताओं के दौरान 'प्रतिकर' में उलट शुल्ट संरचना को रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत: एस. के. मोहंती (2013) के अध्ययन, मंदी द्वारा आंशिक रूप से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में विकासशील देशों को भारत के निर्यात के विविधिकरण की जांच', आर्थिक सर्वेक्षण के लिए पृष्ठभूमि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पर आधारित।

टिप्पणी : विश्लेषण में शामिल आरटीए हैं: इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (आईओआर-एआरसी), क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी/ईस्ट एशियन समिट (ईएएस), बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकॉनामिक कोऑपरेशन (बीआईएमएसटी-ईसी), साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क), इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका इनिशिएटिव (आईबीएसए), यूरोपीय संघ (ईयू), गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी), एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन (आसियान), कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका (सीओएमईएसए), सदर्न कॉमन मार्केट (एमईआरसीओएसयूआर), साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन (एनएसीयू), नार्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (नाफ्टा), एशिया-पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट (आप्टा), साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्यूनिटी (ईएसी), इकॉनामिक कम्यूनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स (डसीओडब्ल्यूएएस), कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआइएस) इकॉनामिक कम्यूनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (ईसीसीएएस), इंडिया-श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (आईएसएलएफटीए), इंडिया-सिंगापुर कंप्रीहेंसिव इकॉनामिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (आईएससीईसीए)।

7.48 वर्तमान स्थिति में डब्ल्यूटीओ वार्ता बंद होने पर विश्व व्यापार धीमा पड़ गया है और संरक्षणवादी उपायों का साया मंडरा रहा है, क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकीय तौर पर सघन वाले निर्यातों के विविधिकरण की रणनीति व्यापार उदारीकरण के साथ व्यापार संवर्धन को और आगे ले जा सकती है। (बॉक्स 7.6)

बॉक्स 7.7 : भारत के व्यापार को पुनर्जिवित करना व बढ़ानाः सूक्ष्म, क्षेत्र-एवं पत्तन-विशेष मुद्दे

सूक्ष्म, क्षेत्र-विशेष एवं पत्तन-विशेष स्तर पर कुछ व्यापार संबंधी मुद्दे एवं सुझाई गई नीतियां निम्नवत हैं।

अवसंरचना संबंधी: भारत के बेहतरीन पत्तनों में भी सिंगापुर, रोटरडैम और संघाई जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिक नहीं हैं। पत्तन अवसंरचना मुद्दों में सड़कों और पत्तन तक जाने वाले मार्गों की खराब स्थिति, भीड़-भाड़, पोत लंगर में देरी, माल प्रबंधन की खराब तकनीकी और उपकरण शामिल हैं जिसके कारण बहु प्रबंधन, बढ़ी हुई समय-सीमा, उच्च लेनदेन लागत बढ़ती है और इस प्रकार बाजार प्रतिस्र्धात्मकता की हानि होती है।

पत्तन-विशिष्ट अवसंरचना मुद्दों में चेन्नई पत्तन तक पहुंच बिंदु में प्रतिबंध, विभिन्न अधिभार जैसे कि भीड़-भाड़ अधिभार और चेन्नई पत्तन के प्रयोक्ताओं पर चेन्नई व्यापार वसूली प्रभार, डिब्बा स्थानांतरण प्रभार, असंतुलन प्रभार आदि शामिल हैं, जिसे व्यापार घटक के काफी कम होने पर और मुंबई में जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) पत्तन पर काफी कम भीड़ होने के बावजूद बिना किसी कानूनी स्वीकृति के प्रभारित किया जाता है, प्रवेश द्वार के समयपूर्व बंद होने के कारण निर्यातित माल बहुत अधिक लागत पर बफर यार्ड में डाल दिया जाता है और इससे लदाई में विलंब और अपनी अगली समुद्रयात्रा पर सुपुर्द करने के लिए डिब्बों को ले जाने वाले कई जहाज, जो जेएनपीटी पत्तन के बाहर जाते हैं, और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल विलंबित होता है।

व्यापार सरलीकरण उपायः यद्यपि भारत 'व्यवसाय करने में सहज' में 132 स्थान पर है, 'सीमापारीय व्यापार' पर प्रथम स्थान सिंगापुर और 68वें स्थान पर चीन के साथ भारत 127 स्थान पर है। भारत को निकासी के लिए 16 निर्यात दस्तावेजों की आवश्यकता है जबकि चीन को 5 की आवश्यकता है और फ्रांस को अच्छी आर्थिक परंपरा के साथ 2 दस्तावेजों की आवश्यकता है। भारत के लिए निर्यात का समय 16 दिन हैं और डेनमार्क के लिए पांच दिन हैं। निर्यात की लागत चीन में 500 डालर और मलेशिया में 450 डालर की तुलना में भारत में यह 1095 डालर प्रति डिब्बा है। भारत में निकासी आयात दस्तावेजों की संख्या 9 है जबकि यह चीन में 5 और फ्रांस में 2 है। भारत में आयात का समय 20 दिन और सिंगापुर में 4 दिन है। भारत में आयात की लागत प्रति डिब्बा 1070 डालर है, चीन में 545 डालर और सिंगापुर में 439 डालर है। कई व्यापार सरलीकरण उपाय हैं, जो सरकारी खजाने पर किसी लागत के बिना निर्यात क्षेत्र को मदद कर सकते हैं। इनमें बहु प्रलेखीकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है क्योंकि किसी निर्यातक को काई निर्यात संव्यवहार पूरा करने के लिए औसतन लगभग 130 जगह पर हस्ताक्षर करना होता है। इन प्रक्रियाओं और लागतों को अल्पतम तक कम करने की आवश्यकता है।

अन्य प्रक्रियात्मक और प्रलेखीकरण सुधारों में निर्यात संवर्धन (ईपी) नौवहन बिलों के प्रतियों के मुद्रण और प्रमाणन की प्रणाली को समाप्त करना, डिब्बा भाड़ा स्टेशनों (सीएफएस) के लिए 24ग7 प्रणाली का कार्यान्वयन, शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात के लिए वचन पत्र (एलयूटी) के नवीकरण से संबंधित अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करना, विदेशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से एल/सी के लिए बैंकों द्वारा आग्रह की प्रथा को हतोत्साहित करना, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) और विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना का विलयन या सरलीकरण, ईपीसीजी योजना के तहत वार्षिक औसत निर्यात उपलब्धि शर्त को हटाना और व्यापार मुकदमेबाजी के मुद्दे का समाधान शामिल है।

कुछ पत्तन-विशिष्ट व्यापार सरलीकरण उपायों में उच्च टर्मिनल प्रबंधन प्रभार (टीएचसी) और बंद करने, जिसके कारण डिब्बे अभिप्रेत जहाजों में नहीं रखे जाते हैं, के समय में वृद्धि और वल्लापदम पत्तन में अंतर्राष्ट्रीय डिब्बा पोतांतरण टर्मिनल (आईसीटीटी) में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) सुविधा की अनुपलब्धता; मूल्यवान माल सीमाशुल्क निकासी केन्द्र (पीसीसीसी), मुबई के सीमाशुल्क कार्यालय के समय को कारगर बनाना क्योंकि यह 1.30 बजे तक खुला रहता है जबकि निर्यात के लिए वस्तुओं/पार्सलों की प्राप्ति के लिए समय 4.00 बजे तक है; और कोलकाता हवाईअड्डे पर गैर-न्यायिक स्टैंप पर वचन देने की अनावश्यक प्रक्रिया और दस्तावेज कि जेवरातों के निर्यातकों द्वारा मात्रा और गुणवत्ता के बारे में निर्यात दस्तावेज में उल्लिखित तथ्य सही हैं, जबकि हस्ताक्षर निर्यात दस्तावेज निर्यातकों को दृढ़ता और उसी प्रकार से बाध्य करते हैं, के मुद्दे का समाधान।

कर एवं सीमाशुल्क संबंधी: इनमें निर्यातकों को शुल्क कर-वापसी, सेवा कर प्रतिदायों, और केन्द्रीय उत्पादशुल्क छूट के दावों के संवितरण के एक समय-सीमा नियत करना शामिल है क्योंकि इन दावों को जारी करने में विलंब, प्रचालन पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिससे वे कम प्रतिस्पर्धी होंगे; केन्द्रीय उत्पादशुल्क छूट दावों का भुगतान सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में क्रेडिट करना; विदेशियों द्वारा भारत में खरीद के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रतिदाय प्रणाली की शुरुआत करना जो विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में क्रय को बढ़ा सकता है; और भारत-थाईलैंड एफटीए के तहत उलट शुल्क संरचना की समीक्षा करना क्योंकि थाईलैंड से तैयार जेवरों का आयात भारत में उपलब्ध प्राथमिक सोने (कच्चे माल) से सस्ता है।

***स्रोतः* एच.ए.सी. प्रसाद, (2012) 'उभरती हुई वैश्विक आर्थिक स्थितिः भारत के व्यापार पर इसका प्रभाव और कुछ नीतिगत मुद्दे, आधार पत्र सं. 1/2012-आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।**

चुनौतियां एवं संभावना

संभावना

7.49 विश्व व्यापार और भारत के व्यापार की संभावना अभी तक अनिश्चित है। विश्व एवं भारत के कुछ महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार जैसे कि यूएसए, चीन और हांगकांग के आयात विकास दर के साथ कुछ नए अंकुर उभरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो पिछले दो माह में ऊपर की ओर हल्का सा झुकाव दर्शा रहा है। तथापि, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स (बीडीआई) जो विश्व व्यापार की मजबूती का एक अच्छा प्रतिनिधि है और जो 19 मई 2008 को 11709 के अपने शीर्ष से गिरना प्रारंभ हुआ (पिछले पांच वर्षों में), वह आधा तक भी नहीं संभला है (आंकड़ा 7.7)। बीडीआई में पुनःप्राप्ति की

नवम्बर-दिसम्बर 2012 जैसे हाल की छोटे दौर की पुन:प्राप्ति, जो हाल के महीनों में उच्च में शामिल है, की तुलना 2008 के उच्च के साथ नहीं की जा सकती है। यहां तक कि यह सुधार भी थोडे समय के लिए रहा, जो जनवरी, 2013 की शुरूआत में नीचे चला गय जिससे यह 2 जनवरी 2013 को 698 के निम्न स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद से बीडीआई इसके 792 के वर्तमान स्तर (28.1.2013) तक मामूली रूप से सुधरा है।

7.50 यह संकेत करता है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद व्यापार पर आश्रित भारत के उत्पाद व्यापार और नौवहन सेवाओं के लिए संभावनाएं अभी अनिश्चित हैं। यद्यपि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि पिछले दो से तीन माह में यूएस, हांगकांग, सिंगापुर और चीन जैसे हमारे व्यापार भागीदारों के आयात विकास दर में कुछ वृद्धि हुई है, हाल के महीनों में भारत से उनके आयात के वृद्धि दर को देखने से एक मिलीजुली तस्वीर दिखाई देती है। जहां 2012 (जनवरी-नवम्बर) में भारत से यूएस एवं जापान का आयात क्रमश: 12.6 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा वहीं 2012 (पूर्ण वर्ष) में चीन और हांगकांग का भारत से आयात क्रमश: 19.6 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत तक कम हुआ तथा भारत से सिंगापुर का आयात 2012 (जनवरी-नवम्बर) में 8.3 प्रतिशत तक कम हुआ।

7.51 दूसरी ओर सोने के आयात (सरकार द्वारा नीतिगत उपायों के फलस्वरूप) में कमी के बावजूद आयात मितव्ययता सीमित रही क्योंकि सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अभी भी काफी अधिक है और तेल का मूल्य 110 यूएस डालर प्रति बैरल के निशान पर बना हुआ है।

7.52 सेवा निर्यात वृद्धि भी इसी प्रकार वैश्विक विकास पर निर्भर होने के कारण वैश्विक संकट काल के बाद व्यापार काफी अस्थिर रहा है। दूसरी ओर, यदि सेवाओं का आयात जारी रहा और सेवाओं में व्यापार का सकारात्मक संतुलन 2012-13 के पूर्वार्ध में गिरना जारी रहा तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए उपलब्ध शक्ति सीमिति होगी।

चुनौतियां

7.53 व्यापार के मोर्चे पर भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। यद्यपि भारत ने अपने निर्यात बास्केट को सफलतापूर्वक विविधतापूर्ण कर लिया है, उत्पाद विविधिकरण के मोर्चे पर और भी कुछ करने की आवश्यकता है। इसे कपड़ा, चमड़ा और चमड़ा निर्माण जैसे मजबूती के परांपरागत क्षेत्रों में स्वयं को पुन:स्थापित करना होगा जिसमें इसे काफी क्षति हुई है, साथ ही इसे नए क्षेत्रों में सशक्त प्रयास करना होगा। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के रूकने और आरटीए के बढ़ने से भारत को भी अधिक महत्वपूर्ण आरटीए में संभावित प्रौद्योगिकी प्रधान मदों पर केंद्रीत रणनीतिक क्षेत्रीय व्यापार नीति की अनुसरण करना होगा। हालांकि भू राजनैतिक विचार महत्वपूर्ण है, भारत को अपने क्षेत्रीय व्यापार वार्ताओं में और अधिक मोल-भाव करना पड़ सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां आबादी की विशाल संख्या के जीवनयापन का संबंध हो। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा और रसायन जैसे क्षेत्रों एवं कुछ एफटीए/आरटीए के कारण क्रत्रिम उलट शुल्क संरचना का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है (बॉक्स 7.6 भी देखें)। सेवा मोर्चे पर, स्वास्थ्य पर्यटन सहित पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों की खान दोहन की प्रतीक्षा कर रही है।

7.54 हाल के वैश्विक मंदी ने पिछले वर्ष उसी माह में 50 प्रतिशत से अधिक की काफी उच्च विकास दर की तुलना में निर्यात वृद्धि मई 2012 से निरंतर नकारात्मक होने के कारण भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी की है। सरकार के पास सीमित राजकोषीय अंतर होने और व्यापार भागीदारों द्वारा संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि के साथ बचा हुआ नीतिगत विकल्प सूक्ष्म स्तर पर है (बॉक्स 7.7 देखें)।

7.55 इस प्रकार कई सूक्ष्म, पत्तन-विशिष्ट और क्षेत्र-विशेष मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये अवसंरचना, व्यापार सरलीकरण, कर एवं प्रशुल्कों और क्रेडिट से संबंधित हैं तथा इन्हें लघु अवधि एवं मध्यावधि में वास्तव में सुलझाया जा सकता है। इन मुद्दों का समाधान, जैसा कि वर्तमान में सरकार द्वारा किया जा रहा है, भारत के निर्यात विकास को तीव्रता से बढ़ा सकता है।